हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

18 मार्च, 2008

खण्ड 1, अंक 8

अधिकृत विवतरण

विशय सूची

मंगलवार, 18 मार्च, 2008

	पृश्ठ संख्या
तारांकित प्र न एंव उत्तर	1
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर	31
अनुपस्थिति की अनुमति	34
बिजनैस एडवाईजरी कमेटी की रिपोर्ट में सं ाोधन	34
वर्श 2008–09 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करना	35

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 18 मार्च, 2008

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर 1, चण्डीगढ़ में प्रातः 09.30 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री रघुवीर सिंह कादियान) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now questions hour.

Construction of Roads in Rhiwani

*** 874. Dr. Shiv Shankar Bhardwaj :** Will the P.W.D. (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the following roads in Bhiwani

(i) Village Nangal to Ajitpur;

(ii) Village Dhana Narsan to Bhiwani;

(iii) Village Jharvai to Lohari;

(iv) Village Haluwas to Mukti Dham Haluwas Gate Bhiwani;

(v) Village Dhana Narsan to Ajitpur;

(vi) Village Roop Gath to Dhani Janga (Luharerei);

(vii) Village Roop Garh to Dhirana ; and

(viii) Village Haluwas to Dhana Ladanpur?

Irrigation Minister (Capt. Ajay Shigh Yadav) : Sir, out of eight roads, one road mentioned at Sr. No. (iii) from Village Jharvai to Lohari already stands constructed. There is no proposal at present with the department to construct the remaining roads.

Dr. Shiv Shankar Bhardwaj : Ms. Speaker Sir, the number of roads which have already been enlisted, are very essential. I would request the Hon'ble Minister that if not all roads, few roads must be completed by the PWD (R&R) and rest may be completed by the Marketing Board. स्पीकर सर, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपने सवाल में आठ सड़कों का जिक्र किया है, उनमें से गांव ढाना नारसन से ाीवानी की सड़क विलेज हालूवास टू मुक्ति धाम हालूवास गेट टू भिवानी, विलेज ढाणा नारसन टू अजीत पुर, विलेज रूपगढ़ से ढाणी जंगा तक दी गई हैं। अध्यक्ष महोदय, इसमें ऐसा है कि यह सडत्रक 33 फुट का कन्सोलिडे ान पाथ है। विलेज ढाणा नारसन से हालूवास तक तो आधे पो र्ान में 33 फुट का पाथ है लेकिन बाकी के ऐरिया में पाथ नही है। इनकी जो दो सड़कें है विलेज नांगल टू अजीत पुर, झारवई से लोहारी और रूपगढ़ से ढाणी जंगा है इसमें केवल 22 फुट का रास्ता है और सरकार की नीति के मुताबिक 22 फुट का जहां रास्ता है वहां पर लैंड ऐक्विजी ान में काफी पैसा लगता है। स्पीकर सर, मैं

माननीय साथी को इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में अभी विचार नहीं कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर यह भी कहना चाहता हूं पिछली सरकार के भाासनकाल के दौरान में कुल 250 किलोममीटर सड़कें बनी थीं और मौजूदा सरकार ने 328 किलोमीटर सड़कें अपने तीन साल के कार्यकाल में बना दी हैं। मैं माननीय इन्दौरा साहब का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि इनकी सरकार के समय में कुल 250 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ था जबकि हमारी सरकार के तीन साल के कार्यकाल के दौरान 328 किलोमीटर सड़कें बन चुकी है और 421 किलोमीटर सड़कों का काम अण्डर प्रोग्रैस है यानि सात सौ किलोमीटर से अधिक सड़कें बना दी जाएंगी। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी की मन ाा रहती है कि हरेक क्षेत्र में प्रदे ा का बराबर विकास हो। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कई सड़कें ऐसी बताई हैं जो बननी बहुत जरूरी हैं। मैं इनके बारे में माननीय सदस्य से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वे एक जरूरी सड़क का नाम बता दें सरकार उसको बनाने बारे विचार कर सकती है।

डॉ. ि ाव भांकर भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करता हूं कि एक सड़क तो काफी कम है इसलिए कम से कम दो सड़कें तो जरूर बनवा दें। रूपगढ़ से ढाणी जंगा की अपनी पंचायत नहीं है और रूपगढ़ के साि उनकी ग्राम पंचायत है। मेरा कहना तो यह है कि

रूपगढ़ टू ढाणी जंगा की रोड़ अगर बनवा देंगे तो उससे वहां के ग्रामवासियों को काफी फायदा हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि नांगल टू अजीत पुर विपेज की जहां तक बात है, उस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि हमारे आदरणीय श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला नांगल गांव में गए थे वहां पर मेरी कांस्टीच्यूएंसी में उनका प्रोग्राम था। वे मेरे हल्के के कई गांवों में गए थे और उन्होंने वहां पर अनाऊंसमैंट भी की थी कि गांव नांगल से अजीतपुर तक सड़क हम बनवा देंगे। इसमें कच्चा रास्ता पहले से ही एग्जिस्ट करता है। इन दोनों सड़कों के लिए तो आपसे प्रार्थना है कि पी.डब्ल्यू.डी (बी.एण्डआर.) से बनवाने की कृपा करें और बाकी की जो सड़कें हैं क्या उनको मार्कीटिंग बोर्ड से बनवाने की कृपा करेंगें ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, जहां तक नांगल से अजीतपुर रोड़ का सवाल है, यह सड़क तकरीबन 3.20 किलोमीटर लम्बी सड़क है और इस पर 22 फुट का कंसोलिडे ान पाथ अवेलेबल है। उस रोड़ के लिए लैण्ड ऐक्वीजी ान पर 93 लाख रूप्ये लगेंगे और 179 लाख रूप्ए उसकी कंस्ट्रक ान पर लगेंगे। यह रोड़ फीजिबल नहीं है क्योंकि इस सड़क को बनाने में काफी पैसा खर्च होगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि हरेक क्षेत्र का बराबर का विकास हो, इस बात को देखते हुए जो उन्होंने रूपगढ़ से ढाणी जंगा रोड़ की बात कही है, उसको जरूर सरकार बनवा देगी। यह मैं माननीय सदस्य को आ वासन

देना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि मौजूदा सरकार की मं ाा है कि सड़कों की मैनटेनैंस और रिपेयर अच्छी तरह से की जाए। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने अपने पांच साल के कार्यकाल में मैनटेनैंस और रिपेयर पर 1744 करोड़ रूप्यें खर्च किए थे और हमारी सरकार ने इन 3 साल के कार्यकाल में मैनटेनैंस, रिपेयर और न्यू कंस्ट्रक ान पर 2100 करोड़ रूपये खर्च किए है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कों पर पिछली सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में 100 करोड़ रूप्ये से कम खर्च किए थे और मौजूदा सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कों पर 700 करोड़ रूप्ये खर्च किए है और इसमें 2007–08 में 360 करोड़ रूपये की मंजूरी मौजूदा सरकार को मिली है। अध्यक्ष महोदय, एन. सी.आर. में पिछली सरकार ने अपने 5 सालों में सड़कों पर 65 करोड़ रूपये खर्च किए थे और इसके मुकाबले हमने 2007–08 में 1200 करोड़ रूपये सैक ान करवाए है। नाबार्ड के इन्होंने मात्र 5 सालों में सड़कों पर 30 करोड़ रूप्ये ही खर्च किये थे और हमने अपने इन 3 सालों में सड़कों पर 250 से 300 करोड़ रूपए खर्च कर दिए है। अध्यक्ष महोदय, अब चाहे बिल्डिंग्ज हों, ब्रिजिज हों या दूसरी चीजें हों यह सरकार उनको बनवा रही है।

डॉ. ि िव भांकर भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, इस सरकार की मं ाा है कि जो भी अनाऊंसमैंट करते हैं या नींव पत्थर रखते हैं उसको ये जरूर पूरा करेंगे। यह जो नांगल टू

अजीतपुर सड़क है उस बारे में माननीय मंत्री श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी जब वहां पर गए थे तो उस बारे में अनाऊंस कर के आए थे कि वे इस सड़क को बनवाएंगें। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि इस सड़क को ये जरूर बनवाएं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, बार यह है कि कई बार मुख्यमंत्री जी को और मंत्रियों को अनाऊंसमैंट करनी पड़ जाती है लेकिन जब बाद में डिपार्टमैंट उस बारे में एग्जामिन करवाते है तो उसमें कई दिक्कतें सामने आती है जब उस बारे में मुख्यमंत्री जी को बताया जाता है तो मुख्यमंत्री जी भी कह देते है कि इसको छोड़ दो। अध्यक्ष महोदय, माननीय डॉक्टर साहब जिस सड़क के बारे में कह रहे हैं यह सडत्रक 3.5 किलोमीटर लम्बी है और उसको बनाने पर एक करोड़ 5 लाख रूपये कास्ट आएगी। वहां पर लैंड इक्वीजी ान की दिक्कत आ रही है और वहां पर मिट्टी भी बहुत दूर से लानी पड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, उसमें कास्ट फैक्टर बहुत ही ज्यादा है। आप वहां पर लैंड दिलवा दें तो हम उसको बनवा देंगे।

श्री फूल चन्द मुलाना : स्पीकर सर, मंत्री जी बहुत ही काबिलियत से जवाब दे रहे है। इन्होंने ि ाव भांकर भारद्वाज जी को बताया कि अनाऊंसमैंट प्रोग्रामों को भी कई बार कैंसिल करना पड़ता है। मंत्री जी, हमारी सरकार ने कई–कई गांवों को एक–एक या दो–दो सड़कें दे दी है। लेकिन मंत्री जी को याद होगा कि कई लोग ढाणियों में बसे हुए है। उन ढाणियों को सड़कों से

जोड़ने का काम कब तक यह सरकार पूरा कर देगी ताकि वहां के लोगों को भी कुछ राहत मिल सकें।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, सभी ढाणियों को सड़कों से जोड़ा जाए यह पोसिबल नही है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मुलाना जी हमारी पार्टी के अध्यक्ष भी है और मुख्यमंत्री जी से ये अपने काम करवा लेते है और मेरे दोस्त भी है। हमने इनके यहां पर कई सड़कें मंजूर की हैं और इसके बावजूद भी इनकी कोई सड़क रिपेयर करवाने की है या बनवाने की है तो हम इनका पूरा ध्यान रखेंगे।

श्री फूल चन्द मुलाना : आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

डॉ. सु गील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे मेरी सीट का माईक खराब होने की वजह से दूसरी आगे वाली सीट पर से बोलने की परमि ान दी। अध्यक्ष जी, मैं यह कह रहा था कि माननीय मंत्री जी सवाल के जवाब में बड़े दबंग दावे कर रहे थे और रिप्लाई देते हुए कह रहे थे कि हमने इतनी लम्बी सड़कें बना दी, इतने करोड़ों रूपए खर्च किए और समान रूप से विकास किया। अध्यक्ष जी, मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि ये पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर है ये मेरे साथ चलें और हमारे यहां पर जो महत्व की सड़कें है उनको देखना चाहें तो देखें कि उनकी हालत क्या है। अध्यक्ष जी, सिरसा से ऐलनाबाद की जो सड़क है उसकी हालत बहुत खराब है। ये बताएं

कि उसको ये क्यों नहीं ठीक करवा पाए ? इसी तरह से कुरला से जाखल की जो सड़क है उसकी भी हालत बहुत खराब है मंत्री जी, क्यों नहीं इस सड़क को ठीक करवा पाए ?

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर साहब, आप स्पैसिफिक क्वै चन पूछें।

डॉ. सु गिल इन्दौरा : अध्यक्ष जी, क्या माननीय मंत्री जी इन सड़कों को प्राथमिकता के तौर पर मजबूत बनाने और रिपेयर करवाने की कृपा करेंगे ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर साहब, मैं पहले ही बता चुका हूं। मैं वि ोश तौर पर बताना चाहता हूं कि जब चौटाला साहब की सरकार थी तो उस दौरान इन्होंने 6 साल तक इस प्रदे ा पर राज किया लेकिन उस समय सड़कों की बहुत बुरी हालत थी। जैसा मैंने बताया कि इन्होंने अपनी सरकार के दौरान पांच साल में केवल 1744 करोड़ रूपये सड़कों की रिपेयर के ऊपर खर्च किए। उस समय ये सारी सड़कें टूटी हुई सौंपकर गए थे। मौजूदा सरकार आने के बाद हमने 2100 करोड़ रूपये इन तीनों सालों में सड़कों की मेंटीनैंस और नयी सड़कों की कंस्ट्रक ान में लगाए है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 700 करोड़ रूपये हम खर्च कर चुके है। इसमें हमने सड़कों को 12 फुट से 18 फुट चौड़ा किया है। अध्यक्ष महोदय, वर्श 2008 में हमने 360 करोड़ रूपये अभी सैंक ान करवाए है। अध्यक्ष महोदय,

चाहे एन.सी.आर. में हो या चाहे नाबार्ड में हो अगर आप इनके समय के मुकाबले हमारे आंकड़े देखें तो आप देखेंगे कि हमने सड़कों पर बहुत कार्य करवाएं है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने दो सड़कों के बारे में जिक्र किया है। सिरसा से ऐलनाबाद और कुरला से जाखल तक की सड़क के बारे में इन्होंने कहा है। अध्यक्ष महोदय, ये मुझे यह बताएं कि क्या आज तक इन्होंने कभी इस बारे में मुझे लिखकर दिया है कि फलाना सड़क मेरे हल्के की खराब है उसको ठीक करवा दीजिए। ये बताएं कि क्या कभी इन्होंने मुख्यमंत्री जी को इस बारे में लिखकर दिया है कि हमारे हल्के की ये नयी सड़कें बनायी जाए ? अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य केवल अपनी बात दर्ज कराने के लिए यहां पर इस तरह की बात करते है ताकि इनकी बात अखबारों की हैड लाईन में आ जाए। ये कभी भी इस बारे में मुझसे व्यक्तिगत तौर पर नहीं मिले और न ही कभी इनकी इस बारे में चिट्टी आयी है इन्होंने आज ही यह मामला उठाया है।

डॉ. सु ील इन्दौरा : अध्यक्ष जी, आज देखें कि मैं आलरेडी पहले सै ान में ही इनको इस बारे में लिखित तौर पर दे चुका हूं। जब मैं यहां पर कह रहा हूं तो लिखकर देने की वैसे भी कोई बात नहीं। अगर हम यहां पर अपनी बात नहीं कह सकते तो फिर सै ान किस लिए होता है ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, एक विधायक का फर्ज यह बनता है कि वह अपने हल्के की देखभाल करें। लेकिन इनके नेता तो दो–दो साल तक विदे ा में रहते है।

श्री अध्यक्ष : इनकी हल्के की जिम्मेवारी नहीं है इनकी तो हरियाणा की जिम्मेवारी है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, यही बात मैं भी कह रहा हूं। वे विपक्ष के नेता तो बन नहीं पाए इसलिए वे दो साल तक विदे ा में ही घूमते रहते है। जिन्होंने जिन दो सड़कों का जिक्र किया है उनके बारे में मैं केवल एक ही बात कह सकता हूं कि हम इनको ऐग्जामिन करवा लेंगे और अगर वे रिपेयर करने लायक हुई तो जरूर उनको रिपेयर करवा देंगे।

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सवाल पूछा और माननीय मंत्री जी ने आ वासन दिया है कि इनकी सड़कों को ठीक करवाएंगे। अध्यक्ष महोदय, बाकी सब बातें तो ठीक हैं लेकिन इन्दौरा साहब बताएं कि जब अभी इनका माईक खराब हो गया था तो ये बोलने के लिए आगे चौटाला साहब वाली सीट पर क्यों नहीं आए, क्या यह उनको करन्ट मारती हैं? ये दूसरी सीट पर तो आगे आकर बोले लेकिन ये चौटाला साहब वाली सीट पर क्यों नहीं आए ? अध्यक्ष महोदय, हम तो चाहते हैं कि ये आगे की सीट पर आ जाएं।

श्री राम कि ान फौजी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि डॉ. ि ाव भांकर भारद्वाज जी ने जो क्वै चन रखा है उसके बारे में मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि करीब 15–20 साल पहले पंचायती राज संस्था की तरफ से मेरे हल्के में कुछ सडक़ें बनाई गई थी, अब उन सड़कों की हालत बहुत ही खराब हैं मेरे हल्के में बवानी खंड़ा से खेड़ी जालब और अलखपुरा तक सड़क बना दी अब उस सड़क को न तो पंचायती राज डिपार्टमैंट बनाता है न मार्किटिंग बोर्ड बनाता है और न ही पी.डब्ल्यू.डी. डिपार्टमैंट इनको बना रहा है। इसके अलावा मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहूंगा कि मेरे हल्के में बोहर से खानक तक किरावड़ से कुंगड़ होते हुए गढ़ी तक नयी सड़क बनाने का कोई प्रावधान मंत्री जी ने रखा हैं ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि कुछ सड़कें पंचायती राज संस्था के द्वारा पहले बनाई गई थीं लेकिन अब ये रिपेयर नहीं हो रही हैं। इस बारे में इनका पहले भी सवाल आया था। मैं इनको बताना चाहूंगा कि 110 सड़कें ऐसी है जो कि पंचायती राज द्वारा बनाई गई थीं जिनको अब हमने टेकओवर कर लिया है जिनमें से 51 सड़कें रिपेयर कर दी है। जिस सड़क का माननीय सदस्य ने जिक्र किया है उसको भी हम रिपेयर कराएंगे, यह मैं ऑन दि फ्लोर ऑफ दि हाउस आ वासन देता हूं। जिन नयी सड़कों के बारे में माननीय सदस्य ने कहा है पहले हम

उनकी फिजीबिलिटी देखेंगे और यह भी देखेंगे कि कंसोलिडे ान वर्क कितने हैं, कितना उसमें पैसा लगेगा तभी मैं उन सड़कों के बारे में हाउस में आ वासन दे सकूंगा या फिर माननीय सदस्य इस बारे में अलग से नोटिस दे दें तो इसको मैं अलग से ऐग्जामिन करवा कर फिर इस बारे में आ वासन दे सकूंगा।

श्री साहिदा खान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मानेसर से तावडू की दूरी मात्र 15 किलोमीटर है और नौरंगपुर, मौहम्मदपुर अहीर और तावडू तक जो सड़क जाती है वह काफी मेन सड़क है और यह सड़क गुड़गांव से जोड़ती है। ये सारे गांव मेन सड़क पर हैं, उनकी हालत बहुत खराब है, सड़कें बिल्कुल जर्जर हालत में पड़ी हैं और इनमें 2–3 ढाणी भी है। क्या मंत्री जी उन सड़कों के बारे में कुछ करने जा रहे हैं ताकि ये सड़कें बन जाएं और मेवात इलाकें की हालत भी थोड़ी बहुत सुधर जाए।

कैप्टन अजय सिंह यादव : आप यह बताएं कि यही सड़के बननी हैं या रिपेयर होनी हैं ?

श्री साहिदा खान : नयी भी बननी है और रिपेयर भी होनी है।

श्री अध्यक्ष : क्या वह एक ही सड़क है जो नयी भी बननी है और रिपेयर भी होनी है।

श्री साहिदा खान : सर, एक सड़क का एक टुकड़ा है जो नया बनना है बाकी की सड़क की रिपेयर होनी है। मैं ज्यादा नाम बताता हूं तो आप नाराज होते हैं इसलिए इकट्ठे हही बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : नाराज कोई नही होता है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो मानेसर से तावडू वाली सड़क का जिक्र किया है, उसके बारे में मैंने कल भी क्वै चन ऑवर के दौरान माननीय सदस्य को बताया था कि 588 करोड़ रूपया मेवात के लिए एन.सी. आर. में हमने मंजूर करवाया है। मानेसर से तावडू जो सड़क है उस पर राजस्थान से बहुत सारे डम्पर आते है। उस सड़क का आधा पो र्न तो ठीक है और जो बाकी का आधा है उसको हम एन.सी.आर. या नाबार्ड की स्कीम के तहत रिपेयर कराएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जब चौटाला साहब की सरकार थी तब बिल्डिंग्स को बनाने का नहीं बल्कि तोड़ने का काम जरूर किया गया था। जो इनका विरोधी होता था उसकी बिल्डिंग ये तोड़ देते थे। (ाोर एवं व्यवधान) इन्होंने बने बनाए मकान तोड़े थे। बिल्डिंग्स पर इनकी सरकार ने साढ़े पांच साल के समय में 450 करोड़ रूपये खर्च किए थे और मौजूदा सरकार ने तकरीबन एक हजार करोड़ रूपये खर्च कर दिए है और करीबन 425 करोड़ रूपये और खर्च करने है। इसके अतिरिक्त एक हजार करोड़ रूपये के काम इस समय चल रहे हैं। इस विधान

सभा भवन का काम भी पी.डब्ल्यू.डी. बी.एण्ड आर. ने किया है इसके लिए मैं वि ोश तौर पर सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा सभी सदस्यों ने विधान सभा के भवन के काम के लिए धन्यवाद किया है लेकिन विपक्ष के साथियों ने तो इस बारे में धन्यवाद भी नही किया है।

श्री बलवंत सिंह सढौरा : हमने पहले ही धन्यवाद किया है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : यह तो अच्छी बात है कि आप कहीं बधाई तो देते है। बहुत मेहनत से हमारे बी.एण्ड आर. के अधिकारियों ने काम किया है।

श्री बलवंत सिंह सढौरा : अध्यक्ष महोदय, हमने धन्यवादी किया है। जबकि कैप्टन साहब कह रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री जी ने धन्यवाद नहीं किया। यह सदन को गुमराह कर रहे हैं हमने इस रेनोवे ान के बारे में धन्यवाद किया है कि यह रिकॉर्ड की बात है। धन्यवाद तो हमने किया है।

श्री अध्यक्ष : सढ़ौरा जी, आपने किया है, इन्दौरा जी ने धन्यवाद किया। आपकी पार्टी के लीडर जो प्रदे ा के मुख्यमंत्री रहे है तजुर्बेकार मैम्बर हैं उन्हें भी धन्यवाद करना चाहिए था कि कितना जबरदस्त तरीके से रेनोव ान किया गया है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं वि ोश तौर से सदन को बताना चाहूंगा कि हमारे बी.एण्ड आर. के

आफिसर्ज ने यह रेनोवे ान का काम किया है। दूसरी बात मैं सदन को बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदे ाानुसार हरियाणा भवन का रेनोवे ान भी चल रहा है जो काफी जर्जर हालात में हो गया था। इसके अलावा प्रदे ा में 70–80 प्रति ात रैस्ट हाउसिज को इस सरकार के आने के बाद रिपेयर करवाया है और ठीक भी करवाया है। मौजूदा सरकार आने के बाद चाहे सड़के हो, चाहे बिल्डिंग्ज की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री रोजगार सड़क योजना की बात हो हमने सभी को रिपेयर करवाया है।

श्री अध्यक्ष : पिछली सरकार के समय कितने रैस्ट हाउसिज को बेचा गया और कितने रैस्ट हाउसिज नीलाम हो गए थे ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने कई रैस्ट हाउसिज को बेचने का काम कर दिया था लेकिन जैसे ही वर्तमान सरकार ने कार्यभार संभाला मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के नोटिस में लाया और कम से कम 20–22 ऐसे रैस्ट हाउसिज जो बहुत ही पुराने रैस्ट हाउसिज थे उन रैस्ट हाउसिज को बचाया है। (विघ्न)

डॉ. सु ील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, **********

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded.

डॉ. सु ील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, **********

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह है कि आदरणीय इन्दौरा जी तजुर्बेकार सदस्य हैं और ये संसद में भी सदस्य रहे है। इन्हें मालूम होना चाहिए कि जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य नहीं है उसके बारे में यहां पर कोई टीका–टिप्पणी करना संसदीय मर्यादा के विरूद्ध हैं फिर भी इन्होंने यह विशय उठाया है। मैं आपकी अनुमति से सदन को बताना चाहूंगा कि सरकार ने पूरे मामले की तहकीकात की है। डॉ. राम प्रका ा जी ने और उनके परिवार के किसी सदस्य ने कभी यह दरख्वास्त नहीं दी कि हमें जमीन का एक्सचेंज करना है। डॉ. राम प्रका ा जी को ग्राम पंचायत का ऑफर गया था। अध्यक्ष महोदय, इस बात के लिए कि उनकी जमीन से ग्राम पंचायत जमीन एक्सचेंज करना चाहती है क्योंकि ग्राम पंचायत की जो जमीन थी वह छ– फीट गहरी थी उस जमीन के अन्दर उस इलाके का सारा पानी इकट्ठा हो जाता था। उस जमीन पर 13 बिजली के खम्बे लगे हुए थे जिसकी वजह से उस जमीन को 5–7 हजार से ज्यादा कोई ठेके पर भी नही लेता था। ग्राम पंचायत ने डॉ. राम प्रका ा जी की धर्म पत्नी को यह प्रस्ताव दिया और उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया क्योंकि यह जमीन उनकी जमीन के साथ लगती थी इसलिए उस जमीन को एक्सचेंज कर लिया। यह भी गलत रिपोर्ट है कि यह सब कार्यवाही एक दिन में हो गई। इस प्रक्रिया के अन्दर एक महीना लगा। इसके लिए बाकायदा ग्राम सभा की मीटिंग बुलाई गई, ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव पास किया, ग्राम सभा ने प्रस्ताव पास किया उसके बाद इन्होंने इस बात को

स्वीकार किया उसके बाद इस जमीन का हस्तांतरण हुआ। फिर भी ये इस बारे में कोई और जानकारी चाहते है तो मेरे पास आ जायें मैं इनको यह सब प्रक्रिया दिखा दूंगा।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जहां तक रैस्ट हाउसिज की बात आई है तो मैं कल आपको सारे आंकड़े दे दूंगा कि इन्होंने कितने रैस्ट हाउसिज बी.एण्ड आर. के और कितने रैस्ट हाउसिज डिपार्टमैंट के बेचने का काम कर रखा था जिन पर हमने आकर रोक लगाई थी इस बारे में मैं सारे फैक्टस कल हाउस में दे दूंगा जिससे पता चल जाएगा कि इन्होंने कितने घोटाले कर रखे थे।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, पंचायत एण्ड डिवैल्पमैंट के चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी महोदय यहां मौजूद हैं, बी.एण्ड आर. के हमारे आदरणीय मंत्री जी भी यहां मौजूद है और ये इरीगे ान के मिनिस्टर भी है। अध्यक्ष महोदय मैं आपसे और माननीय मंत्री महोदय से दरखास्त करूंगा कि कम से कम सदन के पटल पर एक जानकारी अव य रख दें कि कितनी जमीनें पिछली सरकार के कार्यकाल में बेच दी गई और कितनी जमीनें देवीलाल ट्रस्ट को बगैर पैसा लिए तोहफे के तौर पर दे दी गई। यह जानकारी इनको सदन में रखनी चाहिए ताकि सदन को पता चले कि सरकार की बे ाकीमती करोड़ों रूपयों की सम्पत्ति को खूर्द–बुर्द किसने किया and by way of a special mention ये इस चीज को हाउस में लेकर आएं ताकि हरियाणा की जनता को

फैक्चुअल जानकारी पता चले कि इन्होंने क्या–क्या किया। (ाोर एव ंव्यवधान)

ि ाक्षा मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता) : अध्यक्ष महोदय, जींद भाहर में एक धार्मिक जयन्ती देवी मन्दिर है जो गवर्नमैंट के अंडर है। जब ओम प्रका ा चौटाला की सरकार थी उस मन्दिर के पास 4 एकड़ जमीन भाहर के बहुत अच्छे एरिया में थी और बहुत कीमती जमीन थी, इसकी सरकार ने अपने आदमी द्वारा एक घटिया जमीन जिसमें 20 फुट गड्ढे थे उसको परचेज करवाकर उस बढ़िया जमीन से ट्रांसफर करवा दी, इसका भाहर में बड़ा भारी प्रोटैस्ट हुआ था और रिसैंटमैंट हुआ था, इन्होंने तो देवी की भी परवाह नहीं की, भगवान की भी परवाह नहीं की और उस जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करके भाापिंग काम्पलैक्स बनवा कर खड़ा कर दिया। इतना बड़ा अन्याय इनकी सरकार के समय में हुआ था। (ाोर एव ंव्यवधान)

श्री एस.एस. सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा पहले नम्बर पर तारांकित प्र न संख्या 838 लगा हुआ था इस बारे में मेरी आपसे एक रिक्वैस्ट है कि जब मैं सदन की बैठक अटैंड करने के लिए आ रहा था तो उस समय वी.वी.आई.पी. कारकेड गुजर रहा था और जिसके कारण रास्ते में अवरोध लगा हुआ था। इसलिए मुझे वहां पर रूकना पड़ा और मैं लेट हो गया और इसी कारण मेरा सवाल भी लग नहीं पाया। मेरी आपसे हम्बल

सबमि ान है कि मुझे अब अपना सवाल पूछने की परमि ान दी जाए।

Mr. Speaker: Surjewala ji, your request is acceded to. You may ask your question.

Average Rainfall in Haryana

***838. Sh. S. S. Surjewala :** Will the Agriculture Minister be pleased to state-

(a) the average rainfall in various parts of Haryana together with the status of the rainfall both Monsoon and Winter rains during the last five years separately;

(b) whether it is a fact that the Monsoon has changed its course during the last 4-5 years; and

(c) if so, the measure adopted by the Government to help the farmers on this account ?

Agriculture Minister (Sardar H.S. Chatha) : (a) to (c) Sir, the information is laid on the Table of the house.

Information

(a) The District wise average rainfall both Monsoon and Winter rains during last five years in Haryana is annexed at "A"

(b) Yes, there appears to be significant variation in the pattern of the monsoons during the last five years.

(c) Despite deficient rains the state has been able to achieve the highest foodgrain production during 2006-07 i.e. 147.63 lac M.Ts. The Department of Agriculture has undertaken measures for dissemination of better crop management practices and the State Government has ensured adequate power to the farmers for tubewells so that they are able to irrigate their fields in deficient rainfall areas. the Irrigation Department has also taken special steps to ensure adequate availability of canal water for irrigation.

Annexure-A

Year-wise Monsoon and Winter rain for the year 2003 to 2007

(Fig. in mm.)

Year	Monsoon Rains			Winter Rains		
	Actual	Normal	%age Dep.	Actual	Normal	%age Dep.
1	2	3	4	5	6	7
2003-04	608.2	532.5	14	52.2	84.3	-38
2004-05	458.8	535.0	-14	152.8	83.6	82
2005-	523.2	532.3	-2	43.8	83.3	-47

06						
2006-07	326.8	532.7	-39	141.5	83.3	70
2007-08	287.5	532.7	-46	4.7	68.0	-93

District Wise/Year-Wise Monsoon and Winter rain

for the year 2003 to 2005

Year 2003

(Fig. in mm.)

1	2	3	4	5	6	7
Ambala	892.9	818.9	9	90.7	145.2	-37
Bhiwani	381.5	372.2	3	21.4	55.3	-62
Faridabad	936.3	474.9	97	53.5	52.8	2
Fatehabad	395.4	317.3	25	25	58.5	-58
Gurgaon	735	526.9	39	37	59.6	-38
Mewat						
Hisar	513.2	360.5	42	24.3	54.9	-56
Jhajjar	649.2	394.2	65	44.5	49.3	-8
Jind	462.7	452.5	2	45.2	75.9	-41

Kaithal	500	514.7	-3	63.5	82.9	-23
Karnal	411.5	609.7	-32	113.7	122.9	-7
Kurukshetra	392.5	588.8	-33	79.7	106.5	-25
Mohindergarh	320.3	444.1	-28	5.4	58.8	-91
Panchkula	1638	946.4	73	110.7	167.5	-34
Panipat	287.1	536.6	-47	57	78.7	-28
Rewari	787.8	505.7	56	35.8	53.5	-33
Rohtak	748.3	521.4	44	28.5	79.1	-63
Sirsa	250.6	269.5	-7	10.7	50.8	-78
Sonepat	250.6	546.5	-23	39	81.6	-52
Yamunanagar	830.3	936.3	-11	105	171.8	-39
Average	608.2	532.5	14	52.2	84.3	-38

Year 2004

(Fig. in mm.)

1	2	3	4	5	6	7
Ambala	1080.2	810.8	33	204.9	145.2	41
Bhiwani	340.6	372.7	-9	189.7	55.3	243
Faridabad	423.8	470.8	-10	236.9	50.3	374

Fatehabad	229.8	322.7	-29	96.9	58.6	64
Gurgaon	407.6	524.2	-22	176.6	58.8	200
Mewat						
Hisar	281.1	375.8	-25	152.3	54.9	176
Jhajjar	395.5	393.9	5	130.0	47.6	171
Jind	467.4	452.7	3	201.9	76.4	166
Kaithal	631.8	498.3	27	131.0	87.0	51
Karnal	533.3	602.5	-12	148.9	114.1	32
Kurukshetra	468.9	588.6	-20	159.5	106.5	50
Mohindergarh	206.0	463.5	-56	92.5	58.9	58
Panchkula	674.0	946.8	-29	191.5	165.5	16
Panipat	445.8	536.7	-17	101.0	73.5	36
Rewari	379.8	507.3	-25	121.6	54.4	122
Rohtak	328.2	518.9	-37	148.7	79.2	87
Sirsa	208.0	269.6	-23	121.8	50.8	137
Sonepat	470.6	546.4	-14	189.6	82.2	132
Yamunanagar	745.0	936.5	-20	129.5	172.6	-25
Average	458.8	535.0	-14	152.8	83.6	82

Year 2005

(Fig. in mm.)

1	2	3	4	5	6	7
Ambala	943.3	817.6	-15	73.0	144.1	-49
Bhiwani	357.5	372.2	-4	29.0	54.5	-47
Faridabad	519.1	471.1	-10	32.0	53.3	-40
Fatehabad	405.2	317.5	27	48.0	58.5	-19
Gurgaon	575.2	524.4	10	52.0	58.3	-10
Mewat						
Hisar	348.7	360.5	-3	29.0	54.2	-46
Jhajjar	531.3	394.0	35	68.0	46.6	45
Jind	702.7	452.6	55	29.0	76.1	-62
Kaithal	639.1	497.9	28	42.0	86.5	-52
Karnal	455.0	609.7	-25	43.0	113.7	-62
Kurukshetra	429.3	558.8	-27	29.0	106.5	-73
Mohindergarh	281.1	443.2	-37	16.0	58.7	-73
Panchkula	669.4	946.4	-29	87.0	164.9	-47
Panipat	485.5	536.6	-10	12.0	73.3	-54

Rewari	534.0	507.1	5	72.0	53.7	33
Rohtak	514.3	521.4	-1	28.0	78.6	-65
Sirsa	213.2	269.3	-21	80.0	50.2	60
Sonepat	464.1	546.7	-15	10.0	81.3	-88
Yamunanagar	872.4	936.3	-7	54.0	171.6	-69
Average	523.2	532.3	-2	43.8	83.3	-47

Year 2006

(Fig. in mm.)

1	2	3	4	5	6	7
Ambala	581.4	826.2	-30	341.8	144.1	138
Bhiwani	297.1	372.7	-20	95.9	54.5	75
Faridabad	227.0	470.8	-52	91.1	53.3	72
Fatehabad	253.9	317.7	-20	60..3	58.5	3
Gurgaon	261.0	524.2	-50	172.0	58.3	197
Mewat				107.1	58.3	84
Hisar	233.3	360.8	-35	58.3	54.2	8
Jhajjar	316.1	393.2	-20	95.9	46.6	106

Jind	315.9	452.7	-30	167.3	76.1	120
Kaithal	204.0	498.3	-59	116.5	76.5	35
Karnal	271.1	609.5	56	226.2	113.7	98
Kurukshetra	207.3	588.6	-64	208.0	106.5	95
Mohindergarh	132.6	443.5	-70	107.9	58.7	84
Panchkula	659.0	946.8	-30	232.0	164.9	41
Panipat	341.0	536.7	-37	65.3	73.3	-12
Rewari	369.3	507.1	-23	137.2	53.7	154
Rohtak	403.5	521.9	-25	80.0	78.6	1
Sirsa	336.7	269.6	-47	63.9	50.2	27
Sonepat	290.3	546.4	-47	92.9	81.3	15
Yamunanagar	504.9	936.5	-47	306.0	171.6	78
Average	326.8	532.7	-39	141.5	83.3	70

Year 2007

(Fig. in mm.)

1	2	3	4	5	6	7
Ambala	617.5	826.6	-71	18.5	120.1	-85

Bhiwani	240.9	372.2	-35	1.3	46.5	-97
Faridabad	369.2	471.1	-22		44.3	-100
Fatehabad	159.1	317.5	-50	16.2	46.5	-65
Gurgaon	266.6	530.4	-50		50.3	-100
Mewat	276.1	530.4	-48		50.3	-100
Hisar	140.0	360.5	-61	5.3	45.2	-88
Jhajjar	293.4	393.3	-25		39.6	-100
Jind	303.4	452.6	-33		62.1	-100
Kaithal	266.3	497.9	-43		69.5	-100
Karnal	382.7	609.5	-37	4.0	94.7	-96
Kurukshetra	275.2	588.8	-55	8.5	85.5	-90
Mohindergarh	233.5	443.2	-47	1.2	49.7	-97
Panchkula	322.5	946.4	-66	8.5	134.9	-94
Panipat	163.6	536.6	-70		60.3	-100
Rewari	369.9	507.1	-27	8.8	46.7	-81
Rohtak	152.3	521.4	-71	5.5	63.6	-91
Sirsa	156.5	269.3	-42	4.3	40.2	-89
Sonepat	327.0	546.7	-46		67.3	-100

Yamunanagar	431.9	936.3	-54	8.6	142.6	-94
Average	287.5	532.7	-46	4.7	68.0	-93

श्री एस.एस. सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने 2003 से 2007 तक पूरे जिलों की रेनफॉल की इन्फर्मे ान सदन में रखी है। मैं समय बचाने के लिए नमूने के तौर पर कुछ जिलों की पोजी ान पढ़कर सुनाऊंगा। जिन जिलों में ऐवरेज से माईनस रेनफॉल हुई है उनमें है अम्बाला में 49 परसैंट, भिवानी में 47 परसैंट, जीन्द में 62 परसैंट। कुछ जिलों में माईनस 100 परसैंट रेनफॉल हुई है और 7–8 जिलों में माईनस 97 परसैंट रेनफॉल हुई हैं चूंकि मॉनसून ड्रिफ्ट होकर अपना रूख गुजरात की तरफ कर गया था जिसके कारण हमारे यहां न सर्दियों में बारि ा हुई है और न ही गर्मियों में बारि ा हुई है और ये परमानैंट फीचर्स है यह कोई एक साल की बात नही है। अध्यक्ष महोदय, प्रदे ा में जितनी भयानक और अलार्मिंग सिचुए ान है उसको देखते हुए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जो यूनिवर्सिटी है, मौसम विभाग है या एग्रीकल्चर विभाग है क्या इन्होंने पिछले 4 सालों में इस बारे में कोई विचार किया है या कोई योजना बनाई है कि जिससे इस स्थिति का मुकाबला किया जा सके ?

10.00 बजे

सरदार एच.एस. चट्ठा : स्पीकर सर, माननीय साथी ने वाजिब बात कही है कि आंकड़ों के मुताबिक पिछले सालों के दौरान बरसात माईनस में हुई है। बरसात कम होने की स्थिति में एग्रीकल्चर विभाग का यह दायित्व बनता है कि किसानों को घाटा न होने दिया जाए और उन्हें पूरी उपज मिले। अध्यक्ष महोदय, मैं बिजली बोर्ड और सिंचाई विभाग को मुबारकबाद दिए बगैर नहीं रह सकता कि उन्होंने बहुत मेहनत करके किसानों को सिंचाई के लिए पूरी बिजली और पानी मुहैया करवाया है। बिजली बोर्ड ने 8.50 रूपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली खरीदकर किसानों को सिंचाई के लिए सस्ते रेट पर बिजली उपलब्ध करवाई है। अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्वयं सिंचाई विभाग और बिजली बोर्ड की मीटिंग लेकर हिदायतें दी थी कि बरसात की कमी की वजह से किसानों की फसलें नहीं सूखनी चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी की हिदायतों की वजह से ही यह संभव हो पाया है कि बरसात की कमी की वजह से भी किसानों की फसलें नहीं सूखी और उन्हें सिंचाई के लिए बराबर बिजली और पानी मिलता रहा। इसके साथ–साथ एग्रीकल्चर विभाग की तरफ से भी अच्छे सीड किसानों को उपलब्ध करवाये गए। जहां तक मेरे साथी ने एटमोसफियर की बात की है हमारा विभाग एटमोसफियर को नही बदल सकता। एटमोसफियर को देखने का काम दूसरे विभाग का है। हमारा काम यह था कि जो सीड़ पकने के चार–चार, पांच–पाच महीने का समय लेते थे उनके स्थान पर यूनीवसिर्टी ने

नये सीड निकाले हैं जो 10–10 दिन, 15–15 दिन या 20–20 दिन का कम समय पकने में लेंगे ताकि किसानों को जल्दी उपज मिले।

श्री एस.एस. सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने मेरे सवाल का सही जवाब नहीं दिया। सरकार के एफट्र्स के बारे में मैंने कुछ नही कहा है। यह सही है कि किसानों को सरकार की तरफ से पूरी मात्रा में बिजली और पानी उपलब्ध कराने की कोि ा ा की गई है। मेरे सवाल को कृशि मंत्री महोदय मानसून की तरह ड्रिफ्ट कर गये। मेरा सवाल यह है कि इनका विभाग चार साल से सोया पड़ा है। ये बतायें कि इन्होंने क्या किया ? इन्होंने बताया कि इस प्रकार के सीड तैयार किए गए हैं जिनके पकने में 10–15 दिन का कम समय लगता है। इस बारे में भी मुझे डाउट है। मैं भी किसान हूं और मुझे इस प्रकार के सीड के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर ऐसा किया भी है तो यह मेरे सवाल का हल नहीं है। अध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का काम रिसर्च करना है और एग्रीकल्चर विभाग का काम कोओरडीनेट करना है। मौसम विभाग भी काम करता है, अंतर्राश्ट्रीय एजैंसीज भी है लेकिन एग्रीकल्चर विभाग की तरफ से इस प्रकार के सीरियस काम को लाईटली लेना प्रदे ा के हित में नही है।

श्री अध्यक्ष : सुरजेवाला जी, आपका पहल सवाल यह है कि पिछले 4–5 साल से मानसून ने अपनी दि ाा बदल ली है तथा आपका दूसरा सवाल यह है कि इस कारण से किसानों की सहायता करने के लिए सरकार द्वारा क्या–कया उपाय किये गये

है। इस बारे में मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि बरसात कम होने के बावजूद भी इन्होंने किसानों को बिजली और पानी पूरी मात्रा मे मुहैया करवाया है।

श्री एस.एस. सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, आप भी एग्रीकल्चर से संबंध रखते है। इन्होंने कोई एफर्ट नहीं किए और न ही एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने एफर्ट किए। मौसम विभाग ने भी कोआरडिनेट नहीं किया गया। अगर इन्होंने कोई योजना बनाई है तो ये बतायें। आने वाले समय में ये इस प्रकार की गंभीर स्थिति से बिना कोई योजना बनाये कैसे मुकाबला करेंगे?

सरदार एच.एस. चट्ठा : अध्यक्ष महोदय, हमने भार सरकार को इस बारे में कई बार पत्र लिखे है। वहां पर एक्सपर्ट बैठे हैं, वे इस पर कार्यवाही कर रहे है। वहां से इन्स्ट्रक ांज आनी है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन्होंने अपने जवाब में द ार्या है कि हरियाणा में पिछले पांच सालों के दौरान बरसात में कमी हुई है। मंत्री जी मानते है कि बरसात कम होती है और धान जैसी फसल के लिए 1500 मिली लीटर बरसात की जरूरत होती है। एग्रीकल्चर विभाग ने साठी की फसल पर रोक लगाकर या अरली राईस वैरायटी पर रोक लगकाकर बहुत अच्छा काम किया है और प्रदे ा को फायदा पहुंचाया है। क्या मंत्री जी इस

बात पर भी विचार करेंगे कि धान की ज्यादा फसल न बोई जाये खासकर उन एरियाज में जहां पर नहरी पानी सिंचाई के लिए उपलब्ध नहीं है ? क्या सरकार उन किसानों को कोई स्कीम बनाकर देगी जो धान की बिजाई नहीं करेंगे या किसी ओर तरह से उनको कम्पनसेट किया जायेगा? कृपया इस बारे में मंत्री जी जानकारी दें।

सरदार एच.एस. चट्ठा : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि हर साल 10–15 फुट पानी का लैवल नीचे जा रहा है। यही कारण था कि सरकार द्वारा डबल क्रोपिंग धान पर प्यार सुपरबंदी लगाई गई है न कि कानून सुपरबंदी लगाई है। हमारी सरकार ने किसानों को प्यार से समझाया है कि यह बात उनके हित में नहीं है इसीलिये किसानों ने साठी को छोड़ा हैं बाकी जहां तक माननीय साथी ने पैडी को कम करने की बात कही है मैं पर्सनल तौर पर इस बात के हक में हूं कि पैडी की फसल में थोड़ी–बहुत कमी जरूर हो। लेकिन जब तक किसान को कोई अलटरनेटिव नहीं मिलता जितना पैसा किसान को पैडी से मिलता है उतना पैसा उसे किसी और क्रॉप से नहीं मिलता तब तक यह पैडी की फसल कम नहीं होगी।

श्री बलवंत सिंह : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अम्बाला और यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट का जो इलाका है वह सिंचाई के मामले में पूरी तरह से टयूबवैल्स पर निर्भर है। कोई नहर इस इलाके में नही है। मंत्री जी ने अपने

जवा में कहा है कि हमने बहुत बिजली दी है। आज यमुनानगर जिले में गन्ने की बहुत पैदावार होती है उसमें से जमीनदारों का 50 प्रति ात गन्ना पानी न मिलने की वजह से बिल्कूल खत्म हो गया है। बिजली 24 घंटे में सिर्फ दो या ढ़ाई घंटे से ज्यादा पहले भी नहीं मिली और अब भी नहीं मिल रही है। तो क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इस बारे में क्या किया जा रहा है क्योंकि अब फसल पकने के मौके पर है।

सरदार एच.एस. चट्ठा : अध्यक्ष महोदय, मेरे दोस्त सढ़ौरा साहब मुझे हर रोज यहां पर मिलते है लेकिन इन्होंने कभी भी मुझे यह नही बताया कि उनकी फसल सुख गई है। मैं म ाकूर हूं उनका। जहां तक इन्होंने कहा है कि हमारे यहां नहर नहीं है। तो मैं इनको पूछना चाहूंगा कि इनके यहां नहर कहां नहीं है ? यमुनानगर के पास सारी नहरें है और जो नग्गल लिफ्ट इरीगे ान सिस्टम है वह भी है। 6 नहरें तो मैने तब बनाई थी जब मैं मंत्री था। आपके यहां नहरें भी है और आपके यहां टयूबवैल्ज भी है। बहुत ज्यादा एरिया ऐसा है जहां पर सिंचाई का कार्य केवल टयूबवैज्ल के ऊपर निर्भर है तो वहां भी हमने क्रॉप को नुकसान नहीं होने दिया है।

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, बहुत वाजिब सवाल माननीय सदस्य ने उठाया है। यमुनानगर और अम्बाला के जो हमारे इलाके है वहां पर टयूबवैल्ज ही सिंचाई के मुख्य साधन है इसमें वर्शों से सरकारों ने वायदे तो

किए परन्तु अण्डर ग्राऊण्ड वाटर टेबल रिचार्ज हो और पानी का लैवल ऊपर आये इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल कहा था और माननीय सदस्य अगर उस समय मौजूद होते तो भाायद आज यह प्र न ही न आता। तो जो हमारी भााहबाद–दादूपुर–नलवी योजना है अध्यक्ष महोदय, It is for recharge of underground water table. पिछले 20 साल से यह कागजों पर थी। चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार ने इस परियोजना को भाुरू किया। इस समय इसका 60 प्रति ात कार्य वर्क पूरा हो गया है और 30 प्रति ात पक्का स्ट्रक्चर पूरा हो गया है। सरकार इस परियोजना पर 267 करोड़ रूपये खर्च करेगी और यह पूरे इलाके की वाटर टेबल को ऊपर उठायेगी। It is not an irrigation Canal. In its sense, it is for recharge of underground water table of your district.

सिंचाई मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जब ओम प्रका ा चौटाला मुख्यमंत्री थे तो अपने कार्यकाल में उन्होंने इस नहर का ि ालान्यास पत्थर तो रख दिया था लेकिन एक नया पैसा भी उन्होंने बजट में इसके निर्माण के लिए नही रखा और न ही जमीन एक्वायर की थी। अब चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार ने यह परियोजना चालू की। अध्यक्ष महोदय, यह बात मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं।

श्री राम कि ान फौजी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि हमारा तो रेतीला एरिया है इस बार उसमें सरसों की 80–90 प्रति ात फसल पाले के कारण पूरी तरह से खत्म हो गई है। तो मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या वे इसके लिए किसान को राहत के तौर पर कुछ मुआवजा देंगे। इसके अतिरिक्त मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि जैसा कि हमारी सरकार फसलों के अच्छे बीच किसानों को देती है जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि बीज अच्छे होंगे तो फसल भी अच्छी होगी लेकिन इसमें ऐसा होता है कि बीज फसल की बिजाई का समय निकल जाने के बाद मिलता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे तारा–मीरा, चना और दूसरी फसलों के बीच बिजाई के समय किसानों को उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था करें।

सरदार एच.एस. चट्ठा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह वि वास दिलाता हूं और मैं फर्मली हाऊस में भी यह बात कह सकता हूं कि हमने किसान को बीज जल्दी से जल्दी देने की कोि ा ा की है। किसान को बीज मिलने में देरी हुई हो ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान : अध्यक्ष महोदय, कृशि मंत्री जी ने माननीय साथी सुरजेवाला जी के जवाब में डाइवर्सिफिके ान की कही है। डाइवर्सिफिके ान की बात लम्बे अर्से से की जा रही है और यह वैलिड बात भी है कि जहां पर

पानी की कमी है वहां पर हम क्या कर रहे है ? हमारे इलाके में साठी जीरी लगाई जाती थी। मुख्यमंत्री जी ने कई बार साठी जीरी की बुआई को छोड़ने के लिए कहा तो लोगों ने छो दी लेकिन उससे लोगों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ क्योंकि जीरी 20–25 हजार रूपये की होती थी और फिर दूसरी फसल भी बोई जा सकती थी। इस तरह से कहीं न कहीं तो यूनिवर्सिटीज का ही दोश है कि कृशि में इतनी दिक्कते होने के बावजूद भी वे कुछ नहीं दे पा रही है।

सरदार एच.एस. चट्ठा : अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह फसलों की डाइवर्सिफिके ान की जो आपने बात कही है यह बिल्कुल सही है। दूसरी फसलों में इतना पैसा नही होता है जितना कि जीरी में होता है। अब की बार जो जीरी हुई है वह कई जगह तो एक एकड़ में 45–50 हजार रूपये तक हुई है जबकि दाल निकलती है 7–8 हजार रूपए की। यह बात सही है कि किसान को रिम्यूनेरेटिव प्राइस मिलनी चाहिए लेकिन किसान को पूरी कीमत नहीं मिल पाती। जब तक किसान को पूरी कीमत नहीं मिलतती तब तक डाइवर्सिफिके ान करना बहुत मु कल है। डाइवर्सिफिके ान के कारण हमने एक बार सोयाबीन लगवाई थी। वह सोयाबीन किसी ने नहीं खरीदी। जालन्धर की मण्डी में जाकर वह सोयाबीन बिकी थी। यह बात आपकी पूरी तरह से ठीक है कि 25 परसैंट जीरी कम होनी चाहिए लेकिन इसका अलटरनेट आज के दिन हिन्दुस्तान में नही है।

Enhancement in the Sandy Area Water Alowance

***940. Sh. Nirpender Singh Sangwan :** Will the Irrigation Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to enhance the sandy area water allowance from 2.4 per thousand acre area to 3.4 per thousand acre area for the area falling under the Loharu Lift Irrigation Canal System; if so, the time by which the above said proposal is likely to be implemented ?

Irrigation Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) : No Sir, However, Government has restored the water allowance for the Loharu Lift Irrigation Canal System to 3.05 cusecs per thousand acres of the culturable commanded area at outlet head.

मेजर नृपेन्द्र सिंह सांगवान : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि क्या अभी तक हमें जो पानी मिल रहा है वह 2.4 क्यूसिक के हिसाब से ही वे दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : यह जवाब में बता तो दिया है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जो लिफ्ट कैनाल उन सैंडी एरियाज में है। जहां पर लिफ्ट से उठाकर पानी जाता है, उस सैंडी एरियाज में जब इस लिफ्ट कैनाल को बनाने की प्रपोजल बनाई गई उस समय 3.05 क्यूसिक पानी प्रति हजार एकड़ के हिसाब से देने की बात की गई थी। लाइट चली जाती है तो पानी वापिस चला जाता है इससे काफी दिक्कत होती है। जैसा मैंने बताया कि पिछली सरकार के इन लोगों ने अच्छा काम तो

कोई किया नहीं। 2003 में इन्होंने जे.एल.एन. महेन्द्रगढ़ और लोहारू कैनाल में जो कमांड एरिया है उसका 3.05 से 2.4 क्यूसिक पानी प्रति हजार एकड़ कर दिया यानी कम कर दिया। एक तरफ तो भाखड़ा वाटर सर्विसिज का जो कमांड एरिया है वह 80 परसैंट इरीगे ान है, डब्ल्यू.वाई.सी. के अन्दर 65 परसैंट है और दूसरी तरफ हमारे यहां जहां कि लिफ्ट इरीगे ान एरियाज हैं, वहां पर 8 परसैंट इरीगे ान एरिया है। इनके ये हालात है कोई अच्छा काम करने की बजाए उसको ये उल्टा करते है। मौजूदा सरकार ने श्री सोमबीर सिंह जी ने प्र न पूछा था कि इनके एरिया को 3.05 क्यूसिक पानी प्रति हजार एकड़ के हिसाब से किया है जिसकी वजह से लिफ्ट इरीगे ान का हमारा तकरीबन 25 परसैंट भोयर बढ़ेगा। सरकार ने बहुत कदम उठाए है जैसे बी. एम.एल. हांसी बुटाना लिंक ब्रांच का 98 परसैंट काम पूरा हो चूका है। एस.वाई.एल. का अभी हमें पानी नहीं मिल पा रहा है क्योंकि यह केस सुप्रीम कोर्ट में पैंडिंग है जिसकी वहज से हमें पूरा पानी नहीं मिल पा रहा है। पंजाब से हमें भाखड़ा से आगे मूनक पर जो पानी मिलता है वहां भी काफी दिक्कत आती है और हमें पूरा पानी नहीं मिलता है। वहां भी हमारा भोयर 2.4 था और जे.एल.एन. फीडर में दोनों को मिला कर हमारा 3000 क्यूसिक के करीब था उसको घटा कर 1900 क्यूसिक कर दिया था। अब वह बढ़ कर 2405 क्यूसिक हो जाएगा। यानि जिसमें महेन्द्रगढ़ कैनाल, जे.एल. एन. फीडर जिसमें झज्जर के एरिया में लिफ्ट कैनाल है वह बढ़कर 2405 क्यूसिक हो जाएगा। 664 क्यूसिक पानी महेन्द्रगढ़ कैनाल

सिस्टम में है जिसको दो ग्रुप में चलाया जाएगा। उस वक्त इन्होंने वह 518 क्यूसिक कर दिया था। जे.एल.एन. में 463 क्यूसिक हो जाएगा जिसको घटा कर इन्होंने 328 क्यूसिक कर दिया। उसी प्रकार से लोहारू कैनाल प्रोजैक्ट में 538 क्यूसिक हो जाएगा जो कि दो ग्रुप में चलेगा उसको घटा कर इन्होंने 402 क्यूसिक कर दिया था। स्पीकर सर, मेरे कहने का तात्पर्य है कि इतना ही नहीं पानी को सुचारू रूप से चलाने के लिए दादूपुर नलवी प्रोजैक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से भ्रारू हुआ और उसका श्रेय लेने का प्रयास ये पिछली सरकार के श्रीमान् जी कर रहे हैं और कहते है कि इसकी भ्रारूआत इन्होंने की थी। मात्र पत्थर रख कर चले जाओ, न बजट में पैसे का प्रोवीजन करो, न जमीन ऐक्वायर करो तो नहर कैसे बन जाएगी। हमारी सरकार ने न्यू फ्लोर रेट के हिसाब से जमीन का कम्पनसै ान दिया है मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अम्बाला इरीगे ान स्कीम का काम भी हमारी सरकार कर रही है और मेवात कैनाल का काम भी हमारी सरकार कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इन प्रोजैक्टस के पूरा हो जान के बाद किसानों को उनका पूरा हक मिलेगा। स्पीकर सर, पीछे कुछ बरसात कम रही और पंजाब से भी पानी कम मिलता रहा है जिसकी वजह से हम पूरा पानी नहीं दे पा रहे हैं लेकिन हमारी यह कोि ा ा होगी कि जब रेनी सीजन होगा और पर्याप्त मात्रा में हमारे पास पानी होगा तो हम लोगों को पूरा पानी देंगे।

Construction of Mini Secretariat at Ateli Mandi

***934. Sh. Naresh Yadav :** Will the Minister of State for Revenue and Disaster Management be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Mini-Secretariat at Ateli Mandi ?

राजस्व राज्य मंत्री (श्रीमती सावित्री जिंदल) : जी नहीं।

श्री नरे ा यादव : अध्यक्ष महोदय, अटेली कस्बा एक ऐसा जगह है जहां पर कोई सरकारी जगह नहीं है। अटेली के पास खोड़ गांव है जहां पर गांव की पंचायत बस स्टैड के पास जमीन देने को तैयार है। हमारे जितने भी कार्यालय है एक–एक, डेढ़–डेढ़ किलोमीटर के फासले पर छोटे से कस्बे के चारों तरफ पड़ते है। मैं माननीय मंत्री महोदया से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार वहां पर एक मिनी सैक्रेटेरियेट बनाने के बारे में विचार करेगी ताकि सारे सरकारी कार्यालय एक ही स्थान पर इकट्ठे हो जाएं और लोगों को सुविधा हो जाए। इस मिनी सैक्रेटेरियेट के लिए खोड़ में पंचायत जमीन देने के लिए भी तैयार है, क्या वहां पर मिनी सैक्रेटेरियेट बनाया जाएगा ?

श्रीमती सावित्री जिंदल : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगी कि अटेली मण्डी में एक उप–तहसील है और अटेली मण्डी के लोगों के लिए जिला सचिवालय महेन्द्रगढ़ में बना हुआ है। उप–तहसील में उप–तहसील के लिए भवन बनाया जाएगा इसके लिए जमीन आईडैंटिफाई कर

रहे हैं, जगह आईडैंटिफाई करने के बाद वहां पर भवन बनाया जाएगा लेकिन उसका काम अभी मार्कीट कमेटी के भवन में चल रहा है।

Misuse of Red Cross Funds

***915. Sh. Karan Singh Dalal :** Will the State Minister for Revenue and Disaster Management be pleased to state :

a. Whether State Government has received any complaint regarding misuse of Red Cross Funds by Deputy Commissioners or any other officer/official since 2000 till date; and

b. It so, the contents of such complaints alongwith the action taken on the complaints in (a) above ?

राजस्व राज्य मंत्री (श्रीमती सावित्री जिंदल) : विवरण सदन के पटल पर रखी जाती है।

विवरणी

क. जी हां,

ख. एक ि ाकायत समाज कल्याण विभाग से सचिव, जिला रैडक्रॉस भााखा, जीन्द के विरूद्ध प्राप्त हुई थी, जिसका सम्बन्ध एक आडिट पैरा से था जिसमें यह आपत्ति उठाई गई थी कि 15,66,000/– रूपए की लागत से खरीदी गई ट्राईसाईकल आई.एस.आई. मार्का

नहीं थी। जांच उपरांत मामला जिला उपायुक्त–कम–प्रधान, जिला रैडक्रॉस भााखा, जीन्द द्वारा दाखिल दफ्तर कर दिया गया।

एक अन्य ि ाकायत श्रीमती विजय चौधरी पूर्व सचिव, जिला रैडक्रॉस सोसायटी कैथल, जो वर्तमान में जिला रैडक्रॉस सोसायटी पानीपत में सचिव के पद पर पदस्थ है, के विरूद्ध महामहिम हरियाणा के राज्यपाल के कार्यालय से प्राप्त हुई थी। उन्हें आरोपित करके नियमित जांच हेतु जांच अधिकारी की नियुक्ति भी कर दी गई है तथा जांच चल रही है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे सवाल के पार्ट बी का सही जवाब नहीं दिया है। मैंने यह कहा था –

"If so, the contents of such complaints alongwith the action taken on the complaints in 'a' above."

उनकी जो कम्पलेंट थी उसके कटैंट सदन के पटल पर नहीं रखे गये हैं और उनके जवाब में भी भामिल नहीं किये गये है। उन्होंने लिहाजा यह कहा है कि उनके पास ि ाकायत थी। मैं आपके माध्यम से उनसे यह जानना चाहता हूं कि जो इन्होंने पानीपत के लिए कहा, क्या यह सही नहीं है कि उस वक्त के जो डिप्टी कमि नर थे उन्होंने रैडक्रॉस के पैसे से मोबाईल फोन खरीदे थे (विघ्न)। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो पानीपत का जिक्र

किया है उसके बारे में अखबारों में भी आता था और कम्पलेंट यह थी कि उन्होंने रैडक्रॉस के पैसे से महंगे मोबाईल खरीदे और उनका दुरूपयोग किया। अध्यक्ष महोदय, उसका बिल भी रैडक्रॉस के पैसे से अदा किया जाता था। क्या इस बारे में मंत्री महोदया जी को जानकारी है ? अगर नहीं है तो क्या मंत्री महोदया इस बारे में दोबारा से जांच करवाने की कोि ा ा करेंगी ?

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी कर्ण सिंह जी ने जो दोनों कम्पलेंटस के बारे में कन्टैंटस जानने चाले है उस बारे में माननीय मंत्री महोदया दोनों कम्पलेंटस के कन्टैंटस इनको भिजवा देंगी। इन्होंने जो पानीपत के सम्बन्ध में ि ाकायत की बात की है, इस बारे में माननीय मंत्री जी ने स्पश्ट कहा है कि एक कम्पलेंट सैक्रेटरी, डिस्ट्रीक्स रैडक्रॉस, जीन्द के खिलाफ है। यह कम्पलेंट क्या थी इस बारे में स्पश्ट बताया है कि इसमें 15,66,000/– रूपये एन्वालवड थे और यह केस फाईल हो चुका है। दूसरी कम्पलेंट एक्स सैक्रेटरी, डिस्ट्रीक्स रैड क्रॉस सोसाईटी, कैथल को लेकर है। उस बारे में भी हमने जवाब में तथ्य दे दिए है। इसके अलावा इन्होंने पानीपत इण्डियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अधिकारी डिप्टी कमि नर के बारे में चर्चा की है। अध्यक्ष महोदया, इस बारे में माननीय साथी, माननीय मंत्री जी को लिखकर भिजवा दें तो उसकी जांच अव य करवाई जाएगी। अध्यक्ष महोदया, सरकार को

इसमें कोई भी तथ्य छिपाने की जरूरत नहीं है। जो भी दोशी होगा उसके खिलाफ अव य कार्यवाही करवाएंगे।

श्री भाादी लाल बत्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या रैडक्रॉस के अकाऊंटस रैगुलर आडिट होते है ? इसके साथ मंत्री जी यह भी बताएं कि पिछले सालों में डिस्ट्रीक्स वाईज कितने रैडक्रॉस सोसाईटीज के अकाऊंटस आडिट हुए हैं ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, यह पृथक प्र न है और माननीय सदस्य इस बारे में लिखकर भिजवा दें तो इनको इसका जवाब लिखकर दे दिया जाएगा।

श्री भाादी लाल बत्रा : यह पृथक प्र न नहीं है। It is a part of Red Cross. मैंने प्र न रैडक्रॉस के अकाऊंटस कैसे मैनटेन किए जाते हैं, के बारे में पूछा है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य जी को यह बताना चाहूंगा कि हर प्र न जो रैडक्रॉस की फक ानिंग से जुड़ा है वह इस प्र न के अन्दर नहीं आ सकता है। माननीय मंत्री जी के पास इस तरह की हैंडि इन्फर्मे ान नहीं हो सकती है। ये अपने प्र न को माननीय मंत्री महोदया को लिखकर भेज दें और इनको उसका जवाब लिखित में दे दिया जाएगा।

Special Exemption to Women on Domestic Electricity Connection

***890. Dr. Sushil Indora :** Will the Power Minister be pleased to state-

(a) whether any provision of special exemption for the women has been made by the Govt. for releasing domestic electricity cOTh.'1.ection ;

(b) if so, the number of the women in the State who have benefited from such exemption; and

(c) whether any increase in the numbers of domestic electricity connection has been reported due to said electricity exemption ?

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) :

a. No, Sir.

However in compliance to the decision taken by the Govt. of Haryana, concession of 10 paisa per unit for domestic electric connection in the name of women in case that property is owned by women is allowed in the electricity bill.

b. Question does not arise.

c. Question does not arise.

डॉ. सु गील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सरकार का भी धन्यवाद करता हूं कि ये बहुत

ही अच्छी योजना है। लेकिन ये पता नहीं किस तरह से इसको क्रियान्वयन कर रहे हैं कि इसको इम्पलीमैंट नहीं कर पा रहे है। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने सवाल के जवाब में कहा है कि महिलाओं के लिए सरकार 10 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली के बिलों में फायदा दे रही है। इस बारे में जगह–जगह पर बोर्डर्ज भी लगे हुए है। अब इन्होंने जवाब में कह दिया है कि महिलाओं को घरेलू बिजली कनैक ान देने के लिए वि ोश छूट का कोई प्रावधान नहीं है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपने जवाब में कहा है ''यद्यपि, हरियाणा सरकार द्वारा लिए गए निर्णय की अनुपालना में महिला के नाम पर घरेलू बिजली कनैक ान लनै पर ब ार्तें कि सम्पत्ति की स्वयं मालिक होने पर बिजली बिल में 10 पैसे प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है।'' अध्यक्ष महोदय, यह तो इन्होंने प्रावधान के हिसाब से जवाब दे दिया है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, अगर महिलाओं के नाम से प्लॉट नहीं है और यदि वे उसकी स्वामी नहीं है तो इस बारे में भी इनको वर्णन करना चाहिए था। क्या आप इस बारे में बताने का कश्ट करेंगे कि ऐसी कितनी महिलाएं हैं जिनको मकान की स्वामी होने पर स्वयं कितना लाभ पहुंचा है ? साथ में मंत्री जी यह भी बताएं कि ऐसी कितनी लाभार्थी महिलाएं है, जिनको ये लाभ देने जा रहे हैं ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय साभी जो महिलाओं को लेकर स ांय जाहिर की है वह वाजिब है। अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बताना चाहूंगा कि चौधरी भूपेन्द्र

सिंह हुड्डा जी की सरकार ने महिलाओं के कल्याण को लेकर अनेकों कदम उठाये है। जहां तक इन्होंने जो जानकारी चाही हे तो इस विशय में इनको बताना चाहूंगा कि 31 जनवरी, 2008 तक 21,201 महिलाओं ने उत्तरी हरियाणा वितरण निगम में और 35917 महिलाओं ने दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम में यानि की कुल 57118 महिलाओं ने इस स्कीम का जिसमें प्रति यूनिट 10 पैसे की छूट है, लाभ उठाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दस पैसे प्रति यूनिट छूट देने की जो बात की है तो उसके पीछे जो एक सो ाल परपज था, जो एक सामाजिक लक्ष्य था उसको मैं आपकी अनुमति से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा। इन्होंने जो यह कहा कि महिलाएं जा हैं उनके मकान और सम्पत्ति जो उनके पति की है या पिता की भी है, उसकी मल्कियत के अंदर सही मायनों में हिस्सेदारी बने। स्पीकर साहब, इनको तो इस बात की ताईद करनी चाहिए कि आजादी के 60 साल बाद पहली बार श्रीमती सोनिया गांधी जी की सरकार ने महिलाओं को अब तो पैतृक सम्पत्ति के अंदर भी अधिकार दिए है। इसके अलावा जो दूसरी महिला कल्याण की योजनाएं है उनकी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने चर्चा की है अगर ये उस समय सदन में होते तो इनको अव य ही जानकारी मिल जाती।

डॉ. सु ील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया लेकिन मैं इनको बताना चाहूंगा कि इसमें हकीकत यह है कि कुछ भार्तें लगी हुई हैं कि जो मकान है उसकी भी वह

स्वयं मालिक होनी चाहिए। स्पीकर साहब, जैसे हमारे हरियाणा प्रदे ा की कल्चर भी है कि ज्यादातर बाप दादा के नाम से जमीन होती है तो क्या सरकार ऐसी छूट देने का भी प्रावधान करेगी कि अगर महिला मकान की मालिक नहीं भी है तो उसको दस पैसे प्रति यूनिट की छूट मिले ताकि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। महिलाएं अबगर मकान की स्वामी न भी हों तो भी उनको यह लाभ मिलना चाहिए। स्पीकर सर, गांवों में लाल डोरे में किसी के नाम से मकान नहीं होता तो जिस तरह से दस पैसे प्रति यूनिट की छूट है उसमें तो 100 यूनिटस बिजली खर्च करने पर दस रूपये का ही लाभ होगा और इसके लिए भी वे अपने कागज पत्र भी तैयार नहीं कर पाते। स्पीकर सर, आजकल तो बराबरी का अधिकार मांगा जा रहा है लेकिन बराबरी का न सही तो क्या इसमें परैसेंटेज के हिसाब से 20 परसैंट या 25 परसैंट तक महिलाओं को लाभ पहुंचने का काम सरकार करेंगी ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, मैं माननीय सदस्य को आपकी अनुमति से बताना चाहूंगा कि माननीय सदस्य का सवाल महिला स ाक्तिकरण से जुड़ा हुआ ळै जो कि वाजिब है। इनकी चिंता से मैं भी अपने आपको जोड़ता हूं। इस सदन को और खास तौर से चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी को वि ोश रूप से इस बात की चिंता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय सदस्य को फिर बताना चाहूंगा कि दस पैसे प्रति यूनिट महिलाओं को जो बिजली के बिल में रियायत दी थी उसके पीछे

माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ही नि ाना था कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इस प्रकार की जो अनूठी स्कीम्ज हैं, उनके चलते मकान की सम्पत्ति की मल्कियत के अंदर वे हिस्सेदार बनें। जैसा मैंने पहले बताया कि 60 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा अब हुआ है। स्पीकर साहब, डॉक्टर साहब जानते है कि पैतृक सम्पत्ति में हिन्दू अनडिवाइडेड फैमिली में केवल लड़कों को ही सम्पत्ति की मल्कियत के अंदर अधिकार होते थे लड़कियों को कभी यह अधिकार नहीं मिला था। लेकिन श्रीमती सोनिया गांधी की सरकार के द्वारा कानून बदलकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया और एक मु त एक झटके से पूरे हिन्दुस्तान में लड़के और लड़कियों को बराबरी में सम्पत्ति की मल्कियत के अधिकार दिए गए। स्पीकर साहब, इसी तरह से हरियाणा में भी महिला कल्याण की अनेकानेक योजनाएं चल रही है चाहे लाडली योजना हो, चाहे इंदिरा गांधी प्रियद र्नी विवाह भागन योजना हो, चाहे लिंगानुपात की दर को कम करने के लिए सरकार के द्वारा उठाए कारगर कदम हों, चाहे महिलाओं के नाम से सम्पत्ति की रजिस्ट्र करवाने पर दो परसैंट की छूट देने की बात हो तथा चाहे दूसरी अन्य कल्याणकारी योजनाएं हों, वह भी सरकार ने भारू की है।

Ponds dug out under the Rojgar Guarantee Yojna

***857. Dr. Sita Ram:** Will the Chief Minister be please~ to state:-

(a) the names of the Panchayats by whom the ponds have been dug out under the Rojgar Guarantee Yojna in

district Sirsa togetherwith the total amount spent on the digging out a pond; and

(b) the total amount spent on the all works referred to in Part (a) above in district Sirsa ?

Power Minister (Shri Rendeep Singh Surjewala) : Sir, a statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The names ofPanchayats by whom the ponds have been dug under the National Rural Employment Guarantee Scheme (NREGS) in district Sirsa togetherwith the amount spent thereon are given below.

(b) An amount ofRs. 922.449 lacs have been spent on all the works referred to in Part (a) above in district Sirsa.

The Panchayat-wise details are as under :-

Block : Sirsa

Sr. No.	**Name of Gram Panchayat**	**Name of Village**	**No. of Pond**	**Amount Spent (Rs. In Lacs**
1	2	3	4	5
1	Ahmedpur	Ahmedpur	1	0.126
2	Alanoor/Nanakpur	Alanoor/Nanakpur	1	0.430

3	Bajekan	Bajekan	3	5.589
4	Bansudhar	Bansudhar	3	4.275
5	Baruwali	Baruwali	2	4.303
6	Bhamboor	Bhamboor	1	1.640
7	Bharokhan	Bharokhan	4	4.576
8	Chamal	Chamal	3	6.690
9	Darbi	Darbi	1	4.920
10	Dhani 400	Dhani 400	3	1.456
11	Dhani Kheowali	Dhani Kheowali	3	1.390
12	Dhani Rampur	Dhani Rampur	2	0.301
13	Farwain Kalan	Farwain Kalan	3	3.100
14	Farwain Khurd	Farwain Khurd	3	2.600
15	Handi Khera	Handi Khera	4	4.167
16	Jhompra	Jhompra	2	0.464
17	Jhorarnali	Jhorarnali	2	1.570
18	Kanganpur	Kanganpur	2	6.104
19	Kanwarpura	Kanwarpura	2	3.800
20	Kasumbi	Kasumbi	1	1.990
21	Kelnia	Kelnia	1	1.240

22	Kotli	Kotli	1	7.900
23	Madhosinghana	Madhosinghana	2	1.287
24	Mangala	Mangala	2	2.250
25	Mohmadpur	Mohmadpur	1	0.680
26	Moriwala	Moriwala	2	3.970
27	Narel Khera	Narel Khera	2	4.035
28	Nattar	Nattar	1	1.110
29	Patli Dabar	Patli Dabar	2	2.810
30	Phoolkan	Phoolkan	2	1.760
31	Rasulpur	Rasulpur	2	1.911
32	Shahidanwali	Shahidanwali	1	1.680
33	Shahpur Begu	Shahpur Begu	1	1.520
34	Sikander Pur	Sikander Pur	2	8.718
35	Suchan	Suchan	3	4.523
36	Ther B. Sawan Singh	Ther B. Sawan Singh	2	1.454
37	Vaidwala	Vaidwala	1	2.270
	Total		**74**	**108.609**

Block : Odhan

Sr. No.	Name of Gram Panchayat	Name of Village	No. of Pond	Amount Spent (Rs. In Lacs
1	2	3	4	5
1	Anandgarh	Anandgarh	1	2.440
2	Asir	Asir	3	6.180
3	Chatha	Chatha	1	3.550
4	Chormar Khera	Chormar Khera	3	3.380
5	Chukerian	Chukerian	2	5.660
6	Dadu	Dadu	1	6.590
7	Desu Malkana	Desu Malkana	2	6.780
8	Dharampura	Dharampura	1	3.370
9	Ghukanwali	Ghukanwali	4	8.550
10	Hassu	Hassu	1	1.890
11	Jagmalwali	Jagmalwali	2	5.300
12	Jalalana	Jalalana	3	9.800
13	Jandwala Jattan	Jandwala Jattan	3	7.120
14	Kalanwali village	Kalanwali village	2	7.310
15	Khatrawan	Khatrawan	2	0.670

16	Kheowali	Kheowali	2	6.220
17	Khokhar	Khokhar	1	0.620
18	Kingre	Kingre	2	3.640
19	Makha	Makha	2	1.870
20	Malipura	Malipura	3	7.070
21	Mithri	Mithri	2	4.640
22	Naurang	Naurang	1	1.580
23	Nuhianwali	Nuhianwali	1	4.840
24	Odhan	Odhan	4	9.270
25	Panniwala Mota	Panniwala Mota	5	11.400
26	Pipli	Pipli	2	6.650
27	Salam Khera	Salam Khera	1	1.020
28	Singhpura	Singhpura	4	7.840
29	Takhatmal	Takhatmal	1	2.500
30	Tappi	Tappi	3	6.500
31	Taruana	Taruana	2	2.320
32	Tigri	Tigri	2	7.670
33	Tilokewala	Tilokewala	3	7.310
	Total	**Total**	**72**	**171.550**

Block : Nathusari Chopta

Sr. No.	Name of Gram Panchayat	Name of Village	No. of Pond	Amount Spent (Rs. In Lacs
1	2	3	4	5
1	Ali Mohamad	Ali Mohamad	2	10.790
2	Arnianwali	Arnianwali	1	1.900
3	Bakarianwali	Bakarianwali	1	0.960
4	Barasari	Barasari	2	5.760
5	Chadiwal	Chadiwal	4	8.060
6	Chaharwala	Chaharwala	2	5.050
7	Chauburja	Chauburja	2	6.780
8	Darba Kalan	Darba Kalan	1	1.940
9	Dhingtania	Dhingtania	1	3.500
10	Dhookra	Dhookra	1	5.680
11	Ding	Ding	2	8.400
12	Gadli	Gadli	1	1.900
13	Ganja Rupana	Ganja Rupana	2	6.200
14	Gigorani	Gigorani	2	4.600

15	Gudia Khera	Gudia Khera	2	9.000
16	Gusain Wala	Gusain Wala	1	2.500
17	Hanjira	Hanjira	2	4.750
18	Jamal	Jamal	2	4.540
19	Jasania	Jasania	2	1.300
20	Jodhakan	Jodhakan	2	5.250
21	Jogiwala	Jogiwala	2	5.120
22	Jorian	Jorian	1	6.370
23	Kagdana	Kagdana	2	5.000
24	Kheri	Kheri	1	4.900
25	Kukarthana	Kukarthana	1	2.900
26	Kumharia	Kumharia	2	8.900
27	Kutiana	Kutiana	2	4.150
28	Ludesar	Ludesar	2	3.730
29	Makhosarani	Makhosarani	1	1.900
30	Mochiwali	Mochiwali	2	6.000
31	Modia Khera	Modia Khera	2	2.650
32	Nathusari Kalan	Nathusari Kalan	1	6.200
33	Neharana	Neharana	3	10.050

34	Nejia Khera	Nejia Khera	1	1.700
35	Nirban	Nirban	3	5.650
36	Raipur	Raipur	1	3.820
37	Rajpura Keranwali	Rajpura Keranwali	1	0.800
38	Rajpura Sahni	Rajpura Sahni	1	2.000
39	Rampura Bagrian	Rampura Bagrian	1	0.400
40	Rampura Dhillon	Rampura Dhillon	1	2.000
41	Randhawa	Randhawa	2	5.100
42	Rupana Bishonia	Rupana Bishonia	1	0.500
43	Rupana Khurd	Rupana Khurd	1	1.000
44	Rupawaas	Rupawaas	1	4.950
45	Sahuwala-II	Sahuwala-II	1	1.200
46	Shahpuria	Shahpuria	2	7.450
47	Shakkar Mandori	Shakkar Mandori	2	6.800
48	Sherpura	Sherpura	1	2.500
49	Tajia Khera	Tajia Khera	1	2.500
50	Tarkanwali	Tarkanwali	1	4.700
	Total		**79**	**219.800**

Block : Baragudha

Sr. No.	Name of Gram Panchayat	Name of Village	No. of Pond	Amount Spent (Rs. In Lacs
1	2	3	4	5
1	Alikan	Alikan	1	2.880
2	Bhadra	Bhadra	1	1.440
3	Bhangu	Bhangu	2	5.870
4	Biruwala Gudha	Biruwala Gudha	1	3.680
5	Bupp	Bupp	1	1.370
6	Burj Bhangu	Burj Bhangu	2	3.470
7	Burj Karamgarh	Burj Karamgarh	1	1.280
8	Chhatriyan	Chhatriyan	1	1.030
9	Daulatpur Khera	Daulatpur Khera	2	4.390
10	Dhaban	Dhaban	1	0.850
11	Fatehpur Niyamat	Fatehpur Niyamat	3	6.800
12	Jhiri	Jhiri	2	2.380
13	Jhorar Rohi	Jhorar Rohi	2	4.000
14	Kamal	Kamal	1	0.700
15	Karamgarh	Karamgarh	2	3.360

16	Khai Shergarh	Khai Shergarh	3	8.020
17	Khuiyan Nepalpur	Khuiyan Nepalpur	2	3.080
18	Kuranganwali	Kuranganwali	2	2.270
19	Malari	Malari	3	0.990
20	Mallenwala	Mallenwala	4	7.850
21	Mattar	Mattar	1	2.380
22	Nagoki	Nagoki	1	1.750
23	Nezadela Khurd	Nezadela Khurd	3	2.390
24	Panjuana	Panjuana	2	4.460
25	Pucca	Pucca	1	2.350
26	Raghuana	Raghuana	1	6.570
27	Ranga	Ranga	1	0.590
28	Rohan	Rohan	1	1.190
29	Rori	Rori	2	0.550
30	Saharni	Saharni	1	0.750
31	Sahauwala-I	Sahauwala-I	3	3.490
32	Shekhupuria	Shekhupuria	3	4.310
33	Subewala Khera	Subewala Khera	2	3.050
34	Sukhchain	Sukhchain	4	3.430

35	Surtia	Surtia	2	2.300
36	Thiraj	Thiraj	1	0.920
	Total		**66**	**106.190**

Block : Dabwali

Sr. No.	**Name of Gram Panchayat**	**Name of Village**	**No. of Pond**	**Amount Spent (Rs. In Lacs**
1	2	3	4	5
1	Abubsahar	Abubsahar	1	2.900
2	Ahmadpur Darewala	Ahmadpur Darewala	4	26.300
3	Alikan	Alikan	1	8.800
4	Assa Khera	Assa Khera	2	2.850
5	Banwala	Banwala	1	7.000
6	Bharu Khera	Bharu Khera	2	6.300
7	Bijuwali	Bijuwali	2	1.750
8	Chakjallu	Chakjallu	1	2.200
9	Desujodha	Desujodha	1	2.400
10	Ganga	Ganga	6	9.600

11	Goriwala	Goriwala	1	3.450
12	Jandwala Bishnoia	Jandwala Bishnoia	1	6.500
13	Jhutti Khera	Jhutti Khera	1	2.000
14	Jogawala	Jogawala	1	1.400
15	Juttanwali	Juttanwali	1	4.500
16	Kaluana	Kaluana	2	7.070
17	Khuian Malkana	Khuian Malkana	2	4.400
18	Lohgarh	Lohgarh	1	2.700
19	Mangeana	Mangeana	1	1.950
20	Mathdadu	Mathdadu	1	4.300
21	Modi	Modi	1	6.100
22	Moonawali	Moonawali	2	3.900
23	Panniwala Morikan	Panniwala Morikan	1	2.700
24	Panniwala Ruldu	Panniwala Ruldu	1	1.000
25	Phullo	Phullo	2	2.100
26	Rajpura	Rajpura	1	1.700
27	Ramgarh	Ramgarh	1	3.500
28	Rampura Bishnoia	Rampura	2	6.100

		Bishnoia		
29	Ratta Khera	Ratta Khera	1	4.000
30	Risalia Khera	Risalia Khera	1	4.000
31	Sakta Khera	Sakta Khera	1	4.000
32	Sawant Khera	Sawant Khera	1	1.380
33	Shergarh	Shergarh	3	5.720
34	Teja Khera	Teja Khera	1	2.400
	Total		**52**	**156.970**

Block : Rania

Sr. No.	**Name of Gram Panchayat**	**Name of Village**	**No. of Pond**	**Amount Spent (Rs. In Lacs**
1	2	3	4	5
1	Bacher	Bacher	1	1.400
2	Bahiya	Bahiya	2	2.840
3	Bani	Bani	2	4.110
4	Bhoona	Bhoona	1	1.450
5	Chakan	Chakan	3	8.600
6	Dariawala	Dariawala	1	0.220

	Bukharakh	Bukharakh		
7	Dhamora Their	Dhamora Their	1	0.260
8	Dhanibangi	Dhanibangi	1	0.110
9	Dhanoor	Dhanoor	1	2.410
10	Dhottar	Dhottar	1	1.010
11	Dhudianwali	Dhudianwali	1	4.000
12	Fatehpuria	Fatehpuria	1	1.170
13	Gindran	Gindran	1	2.100
14	Gobindpura	Gobindpura	1	0.340
15	Haripura	Haripura	1	1.330
16	Jodhpuria	Jodhpuria	2	5.280
17	Keharwala	Keharwala	2	5.030
18	Khaja Khera	Khaja Khera	1	0.510
19	Kussar	Kussar	2	1.680
20	Mamber Khera	Mamber Khera	3	5.930
21	Mangalia	Mangalia	1	1.230
22	Mattu Wala	Mattu Wala	1	0.840
23	Mehna Khera	Mehna Khera	2	2.790
24	Mohmadpuria	Mohmadpuria	1	1.300

25	Moujdeen	Moujdeen	1	0.200
26	Naiwala	Naiwala	1	0.980
27	nakora	nakora	1	1.700
28	Nathor	Nathor	3	5.140
29	Ottu	Ottu	1	1.110
30	Patti Rathawas	Patti Rathawas	2	6.860
31	Peer Khera	Peer Khera	2	3.170
32	Rampur Ther	Rampur Ther	1	0.450
33	Ranjitpur their	Ranjitpur their	0	0.000
34	Sadewala	Sadewala	1	0.710
35	Sainpal	Sainpal	2	2.260
36	Sultanpuria	Sultanpuria	3	4.050
37	Their Mohar Singh	Their Mohar Singh	1	1.180
38	Ther Shahidanwali	Ther Shahidanwali	1	2.420
	Total		**54**	**86.170**

Block : Ellenabad

Sr. No.	**Name of Gram Panchayat**	**Name of Village**	**No. of**	**Amount Spent (Rs. In**

			Pond	**Lacs**
1	2	3	4	5
1	Amritsar Kalan	Amritsar Kalan	2	1.970
2	Bhuratwala	Bhuratwala	2	4.870
3	Dhani Bachan Singh	Dhani Bachan Singh	1	1.620
4	Dhani Jattan	Dhani Jattan	3	2.340
5	Dhani Kahan Singh	Dhani Kahan Singh	1	0.170
6	Dhani Mauju	Dhani Mauju	1	2.790
7	Dhani Sheran	Dhani Sheran	2	4.480
8	Dharampura	Dharampura	1	2.290
9	Jiwan Nagar	Jiwan Nagar	1	1.550
10	Karam Shana	Karam Shana	2	5.340
11	Kariwala	Kariwala	1	1.590
12	Kashi Ram Ka Bass	Kashi Ram Ka Bass	1	3.130
13	Kheri Surera	Kheri Surera	2	7.450
14	Kotli	Kotli	1	0.480

15	Kumthala	Kumthala	1	0.200
16	Mamera Kalan	Mamera Kalan	2	3.960
17	Mamera Khurd	Mamera Khurd	1	1.000
18	Mauju Khera	Mauju Khera	1	1.230
19	Mirzapur	Mirzapur	2	1.390
20	Mithanpura	Mithanpura	3	2.520
21	Mithi Sureran	Mithi Sureran	3	2.470
22	Neemal	Neemal	1	3.670
23	Partap Nagar	Partap Nagar	4	4.680
24	Poharkan	Poharkan	1	0.970
25	Talwara Khurd	Talwara Khurd	2	7.510
26	Umedpura	Umedpura	2	3.490
	Total		**44**	**73.160**
	District Total		**441**	**922.449**

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा। माननीय सदस्य ने देखा भी होगा क्योंकि जवाब उनको भी सर्कुलेट हुआ है। केवल सिरसा जिले के अंदर ही अकेले तालाब की खुदाई के एक मद में 441 गांव लाभान्वित हुए और सरकार ने इस काम पर 922 लाख 44 हजार 900 रूपये खर्च

किए है। स्पीकर सर, सरकार ने जो वहां पर पक्षपात रहित कारगर उठाए है यह उसका जीता जागता प्रमाण है।

डॉ. सीता राम : स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा है कि राश्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत जिन जिलों में काम भाुरू किया गया है उनमें सिरसा जिला भी एक है। स्पीकर साहब, मैं बताना चाहूंगा कि इस योजना के तहत गांवों के अंदर जो तालाब खुदवाए गए या तो वह पंचायत की उपजाऊ भूमि पर खुदवाए गए या जहां पर पानी पहुंचने के साधन नहीं हैं ऐसी जगहों पर तालाब खुदवाए गए। क्या मंत्री महोदय आ वासन देंगे कि सरकार मामले की जांच कराएगी क्योंकि एक तो इससे पंचायत का नुकसान हुआ है, उनकी आमदनी घटी है और दूसरे इस तरह से तालाब खुदने का कोई फायदा भी नहीं हुआ है ? अध्यक्ष महोदय, राश्ट्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंदर जो मजदूर काम करते हैं उनमें से बहुत से मजदूर हमें यह ि ाकायत करते है कि उनको मजदूरी नहीं मिली है। इस बारे में क्या मंत्री जी कोई आ वासन देंगे ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि ....

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the question hour is over.

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर

Indira Gandhi Paiy Jal Yojna

***839. Sh. Shamsher Singh Surjewala :** Will the Water Supply & Sanitation Minister be pleased to state :-

a. whether Haryana Government had launched "Indira Gandhi Paiy Jal Yojna" from 19.11.2006;

b. if so, the names and number of the Villages covered under the Yojna in the Kaithal Assembly constituency; and

c. the time by which all the villages in Kaithal Assembly Constituency are likely to be covered ?

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) :

क. जी हां, श्रीमान्।

ख. सदन के पटल पर एक स्टेटमैंट रखी है।

ग. कैथल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी गांवों में 30.6.2008 तक कार्य पूरा होने की संभावना है।

स्टेटमैंट

कैथल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में इन्दिरा गांधी पेयजल योजना के अन्तर्गत सम्पन्न किए गए गांवों की स्थिति

क्र.सं.	गांव का नाम	इन्दिरा गांधी पेयजल योजना के अन्तर्गत स्थिति

1	अटेला	कार्य पूरा हो चुका है।
2	लडाना बाबा	कार्य पूरा हो चुका है।
3	बलवन्ती	कार्य पूरा हो चुका है।
4	छोत	कार्य पूरा हो चुका है।
5	ढोढ खेड़ी	कार्य पूरा हो चुका है।
6	दिलुवाला	कार्य पूरा हो चुका है।
7	डावल	कार्य पूरा हो चुका है।
8	डोहर	कार्य पूरा हो चुका है।
9	ढुडरहेड़ी	कार्य पूरा हो चुका है।
10	फरांसवाला	कार्य पूरा हो चुका है।
11	गढ़ी पाडला	कार्य पूरा हो चुका है।
12	गियोंग	कार्य पूरा हो चुका है।
13	गुहना	कार्य पूरा हो चुका है।
14	जगदी ापुरा	कार्य पूरा हो चुका है।
15	जसवन्ती	कार्य पूरा हो चुका है।

16	क्योड़क	कार्य पूरा हो चुका है।
17	खानपुर	कार्य पूरा हो चुका है।
18	खुराना	कार्य पूरा हो चुका है।
19	कुलतारन	कार्य पूरा हो चुका है।
20	माघो माजरी	कार्य पूरा हो चुका है।
21	मानस	कार्य पूरा हो चुका है।
22	पाडला	कार्य पूरा हो चुका है।
23	पट्टी डोगरान	कार्य पूरा हो चुका है।
24	कुतबपुर	कार्य पूरा हो चुका है।
25	फ र्ा माजरा	कार्य पूरा हो चुका है।
26	भोरगढ़	कार्य पूरा हो चुका है।
27	टीक	कार्य पूरा हो चुका है।
28	उझाना	कार्य पूरा हो चुका है।
29	धर्मपुरा (एन.सी.)	कार्य पूरा हो चुका है।
30	देवीगढ़	कार्य पूरा हो चुका है।

31	बरोट	कार्य प्रगति पर है।
32	भानपुरा	कार्य प्रगति पर है।
33	दयोहरा	कार्य प्रगति पर है।
34	पट्टी अफगान	कार्य अलाट कर दिया है।
35	पट्टी खोट	कार्य अलाट कर दिया है।
36	रोहेरियां	कार्य अलाट कर दिया है।
37	सेरता	कार्य अलाट कर दिया है।

Level of Pollutants in Agra and Gurgaon Canal

***883. Sh. Karan Singh Dalal :** Will the Minister of State for Environment be pleased to state –

a. the level of pollutants received at head of Agra and Gurgaon canal of Okhla in all four seasons of 2007-08; and

b. the status of pollutants at Faridabad and Palwal fo the above canals during the same period as in (a) above ?

एन एवं पर्यटन राज्य मंत्री (श्रीमती किरण चौधरी) : (क) एवं (ख) विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

क. 2007–08 की सभी चार सीजनों में ओखला में आगरा तथा गुड़गाव नहर हैड पर उपलब्ध प्रदूशण का स्तर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (बी.ओ.डी.) के सम्बन्ध में केन्द्रीय प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार 3 मिलीग्राम प्रति लीटर की अनुज्ञेय सीमाओं के विरूद्ध 13–37 मिलीग्राम प्रति लीटर की रेंज में है। दोनों नहरों में ओखला में बी.ओ.डी. का उच्च स्तर का मुख्य कारण देहली प्रदे ा में 22 नहरों के माध्यम से बिना साफ किये/आं ाक साफ किए/औद्योगिक/सीवरेज मलों का यमुना नदी में प्रवाहित करना है।

ख. हरियाणा राज्य प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की गई मोनिटरिंग के अनुसार गुड़गाव नहर में बी.ओ.डी. के सन्दर्भ में बदरपुर बोर्डर पर प्रदूशण का स्तर 21–27 मिलीग्राम प्रति लीटर के रेंज में है तथा फरीदाबाद गुड़गांव बोर्डर के समीप गांव बीजपुर पर बी.ओ.डी. का स्तर 19–26 मिलीग्राम प्रति लीटर की रैंज में है तथा हरियाणा यू.पी. बोर्डर पर गांव करमान के समीप बी.ओ.डी. स्तर 17–19 मिलीग्राम प्रति लीटर की रेंज में है।

अनुपस्थिति की अनुमति

Mr. Speaker : I have received a Leave of Absence dated 17th March, 2008 from Shri Balbir Pal Shah, M.L.A. which reads as under :-

" Sir;

I humbly request that leave be granted to me in this Session as per recommendations of the Doctor. The Doctor's advice and certificate is attached herewith. "

Mr. Speaker: Question is –

That the Leave of Absence be granted to Shri Balbir Pal Shah, M.L.A. to remain absent from the sittings of the House during this Session.

Voices: Yes, yes.

The motion was carried.

बिजनैस एडवाईजरी कमेटी की रिपोर्ट में सं ाोधन

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received a communication dated 17th March, 2008 from the Government that the Haryana Appropriation Bill in respect of Supplementary Estimates (2nd Instalment) for the year 2007 - 08 which was to be taken up on 28th March, 2008 may be taken up on 19th March, 2008.

As per the Report of Business Advisory Committee adopted in the House on 7th March, 2008, the Haryana Appropriation Bill in respect of Supplementary Estimates (2nd Instal.'1lent) for the year 2007-08 which was to be taken up on 28th March, 2008 now with the sense of the House, this item of Business may be taken up on 19th March, 2008 and the Report of Business Advisory Committee may be amended and adopted accordingly.

Is it the pleasure was amended and adopted with the sense of the House accordingly.)

वर्श 2008–09 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करना

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Finance Minister will present the Budget Estimates for the year 2008-09.

वित्त मंत्री (श्री बिरेन्द्र सिंह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्श 2008–09 के लिए बजट प्रस्तुत करने जा रहा हूं। वर्श 2005 में दो तिहाई बहुमत के साथ सत्ता में आने के बाद यह कांग्रेस सरकार लगातार चौथा बजट है।

2. हरियाणा के मतदाताओं द्वारा 2005 में भाासन की बागडोर कांग्रेस पार्टी को सौंपे जाने के बाद हमारे प्रयास सतत आर्थिक विकास के लिए अनुकूल माहौल पैदा करने के रहे हैं। मैं सदन का ध्यान जून, 2005 में प्रस्तुत अपने बजट भाशण की ओर दिलाना चाहूंगा, जिसमें मैनें कहा था – ''हमारा परम कर्त्तव्य है कि हम लोगों को स्वच्छ एवं कल्याणकारी भाासन प्रदान करके उनमें वि वास की भावना पैदा करें, जिससे उन्हें भय, आतंक और असुरक्षा से राहत मिलेगी।'' मैं आज इस गरिमामय सदन में गर्व के साथ दावा कर सकता हूं कि हमारी सरकार अपने इन लक्ष्यों पर खरी उतरी है और पूर्ण रूप से कानून का भाासन स्थापित किया गया है। प्रदे ा में भाान्ति, सामंजस्य और सामाजिक सद्भावना कायम है। प्रदे ा में आर्थिक समृद्धि आ रही है और

वित्तीय दृश्टि से हमारा राज्य दे ा के सर्वाधिक सुव्यवस्थिति राज्यों में से एक है।

3. मैं सदन का ध्यान अपने 2005–06 के बजट भाशण की ओर पुनः दिलाना चाहूंगा, जिसमें इस तथ्य पर प्रका ा डाला गया था कि राज्य के चहुंमुखी विकास के लिए पिछली सरकार की कोई विस्तृत दीर्घकालिक नीति न होने की वजह से कांग्रेस सरकार को अनेक कठिनाइयों से जूझना पड़ेगा, संसाधनों में वृद्धि करने के लिए अर्थोपायों की खोज करनी है और भविश्य में संतुलित विकास सुनि ित करने हेतु धन का पुनः आबंटन करना है। ऐसा करके ही हमारी प्राथमिकताएं और प्रतिबद्धताएं पूरी हो सकती है। हमारी पार्टी के चुनावी घोशणा पत्र में वर्णित कांग्रेस सरकार की प्राथमिकताओं पर पिछले तीन बजटों में समुचित रूप से बल दिया गया है और इनके लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। कृशि क्षेत्र पर वि ोश ध्यान देना, उच्चकोटि की ि ाक्षा प्रदान करना, बेहतक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना, सामाजिक क्षेत्र, वि ोशतः समाज के कमजोर वर्गों के स ाक्तिकरण पर बल देना और सुदृढ़ आधारभूत ढांचा तैया करना – ये सब गत तीन वर्शों के दौरान हमारी प्राथमिकताएं रही हैं, जिनके लिए हमने रोड मैप तैयार किया था। अब लक्ष्यों को पूरा करने और लाभों को समुचित रूप से संचित करने का समय आ गया है। हमारे द्वारा इस वर्श और अगले वर्श किए जाने वाले प्रयासों से यह सुनि ित होगा कि आर्थिक विकास की गाथा

अल्पकालिक और अस्थाई न होकर भाा वत व चिरकालिक सच्चाई हो। ये खोखले नारे अथवा दिखावा मात्र नहीं है। हमने आर्थिक विकास की सुदृढ़ नींव रखी है। हमारा वित्तीय प्रबन्धन कौटिल्य द्वारा लिखित 'अर्थ ाास्त्र' के इन सिद्धान्तों पर आधारित है – ''राज्य की सभी गतिविधियां प्रथमतः खजाने पर निर्भर है। इसलिए, एक राजा को इसकी ओर सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए। जिस राजा का खजाना खाली होता है, वह नागरिकों और दे ा को तबाह कर देता है। अर्थ (सुदृढ़ अर्थ–व्यवस्था) सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि धर्म और कर्म दोनों ही इस पर निर्भर हैं .... यदि प्राप्तियों और खर्च पर समुचित ध्यान दिया जाये तो राजा को वित्तीय कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा।''

4. महोदय, हम सही रास्ते पर हैं और हमने राज्य के लिए एक सुदृढ़ वित्तीय प्रबन्धन की नींव रख दी है, जो राज्य के चहुमंखी विकास के लिए भाुभ संकेत है।

आर्थिक परिदृ य

5. वर्श 2007–08 के दौरान अग्रिम अनुमानों के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्यों (1999–2000) पर 101319 करोड़ रूपये होने की संभावना है, जो पिछले वर्श के त्वरित अनुमानों से 10.1 प्रति ात अधिक है। सकल राज्य घरेलू उत्पादन में स्थिर मूल्यों (1999–2000) पर वृद्धि वर्श 2005–06 में 9.2 प्रति ात और 2006–07 में 11.4 प्रति ात थी, जो गत दस

वर्श के दौरान सर्वाधिक वृद्धि दर है। वर्श 2007–08 के दौरान, कृशि क्षेत्र में स्थित मूल्यों (1999–2000) पर 4.5 प्रति ात की वृद्धि होने की सम्भावना है, जबकि राश्ट्रीय स्तर पर यह वृद्धि 2.6 प्रति ात है। चालू वर्श में उद्योग और सेवा क्षेत्र में क्रम ाः 10 प्रति ात और 12 प्रति ात की वृद्धि होने की सम्भावना है, जबकि राश्ट्रीय स्तर पर इन क्षेत्रों की वृद्धि क्रम ाः 9.4 प्रति ात और 10.7 प्रति ात है।

6. वर्श 2007–08 में (अग्रिम अनुमान) वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय 56,280 रूपये होने का अनुपात, जबकि 2006–07 में (त्वरित अनुमान) यह 49038 रूपये थी। प्रति व्यक्ति आय में यह वृद्धि 14.8 प्रति ात है। वर्श 2007–08 में (अग्रिम अनुपात) स्थित मूल्यों (1999–2000) पर प्रति व्यक्ति आय 38720 रूपये होने का अनुमान है, जबकि 2006–07 (त्वरित अनुमान) में यह 35779 रूपये थी। यह वृद्धि 7.6 प्रति ात की राश्ट्रीय वृद्धि के मुकाबले 8.2 प्रति ात है। आज हरियाणा प्रति व्यक्ति आय की दृश्टि से गोवा के बाद दे ा का सबसे बड़ा राज्य है।

राजकोशीय प्रबन्धन

7. हरियाणा राजकोशीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम, जिसका उद्दे य वित्तीय अनु ाासन लाना है, को क्रियान्वित करने में अग्रणी है। एफ.आर.

बी.एम. अधिनियम में व्यवस्था है कि राज्य को राजस्व घाटा 2008–09 तक भून्य के स्तर पर लाना चाहिए, जबकि मुझे इस गरिमामय सदन को यह सूचित करते हुए खु ाी हो रही है कि हमने 2005706 में ही राजस्व अधि ोश प्राप्त करके इस लक्ष्य को बहुत पहले ही प्राप्त कर लिया था। पें ान, छात्रवृत्तियों, बिजली सबसिडी इत्यादि जैसे राजस्व खर्च के लिए भारी आबंटनों के बावजूद अभी भी राजस्व अधि ोश के दर्जे की प्राप्ति संसाधनों के प्रबन्धन में इस सरकार की विवेक ीलता और अनु ाासन का सबूत है।

8. एफ.आर.बी.एम. अधिनियम में व्यवस्था है कि राजकोशीय घाटे को 2008–09 तक कम करके समल राज्य उत्पाद के तीन प्रति ात के स्तर पर लाया जाये और गारण्टियों समेत कुल ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 28 प्रति ात से अधिक नहीं होना चाहिए। परन्तु हमारी सरकार ने एक बार फिर इस निर्धारित लक्ष्य को दो वर्श पहले ही प्राप्त कर लिया है। वित्तीय घाटा, जो 2003–04 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.6 प्रति ात था, को 2006–07 तक कम करके –0.93 प्रति ात किया गया। वर्श 2006–07 के दौरान, कुल ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 25.81 प्रति ात है, जो एफ.आर.बी.एम. अधिनियम की 28 प्रति ात की सीमा से काफी कम है।

9. राज्य सरकार राजस्व घाटै और राजकोशीय घाटे के सम्बन्ध में एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के निर्धारित लक्ष्यों को

प्राप्त करके भारत सरकार से ऋण राहत और ब्याज राहत के रूप में दोहरे लाभ प्राप्त कर रही है। राज्य सरकार को 2005–10 के दौरान 581.43 करोड़ रूपयए की ऋण राहत प्राप्त होने की सम्भावना हैं हमें लाभ मिलने भुरू हो गए हैं और हम यह समस्त लाभ प्राप्त करने के मार्ग पर अग्रसर है। राज्य पर ब्याज का भार, जो 2003–04 में राजस्व प्राप्तियों का 21.46 प्रति ात था, को घटाकर 2006–07 में काम करके राजस्व प्राप्तियों का 12.62 प्रति ात किया गया है।

10. हमने खर्च की गुणवत्ता में भी सुधार किया है। पूंजीगत खर्च, जो परिसम्पत्तियों का निर्माण करता है और जो विकास दर को तेज करता है, 2004–05 में 1105 करोड़ रूपया था। वर्श 2006–07 मे ंइसमें काफी वृद्धि करते हुए इसें 2612 करोड़ रूपए कर दिया गया और यह 2007–08 के सं ाोधित अनुमानों में बढ़कर 3386 करोड़ रूपए होने की सम्भावना है। वर्श 2008–09 के बजट अनुमानों में इसे 3751 करोड़ रूपए तक बढ़ाने का हमारा प्रस्ताव है। राज्य सरकार का भुद्ध ऋण, जो 2003–04 में 2495.24 करोड़ रूपए था, को 2006–07 में काफी कम करके सिर्फ 898 करोड़ रूपये कर दिया गया और 2007–08 में इसकी केवल 46.62 करोड़ रूपए रह जाने की सम्भावना है।

11. 2006–07 के दौरान, राज्य का अपना कुल कर राजस्व पिछले वर्श से 20.37 प्रति ात की वृद्धि दर के साथ 10928 करोड़ रूपए था। वर्श 2004–05 के बाद 2006–07 तक

राज्य के कर राजस्व में 46.88 प्रति ात की वृद्धि हुई है। वि वव्यापी मंदी समेत विभिन्न कारणों से राश्ट्रीय अर्थ–व्यवस्था में आई मामूली कमी के बावजूद मुझे इस वर्श के बजट में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का पूरा वि वास है। हमने 2008–09 के दौरान राज्य का राजस्व के रूप में 14294 करोड़ रूपए की रा ि ा एकत्रित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है और यह राज्य का संग्रह में 2007–08 के 12251 करोड़ रूपए के बजट अनुमानों से लगभग 16.88 प्रति ात की अपेक्षित वृद्धि द ार्ाता है।

वार्शिक योजना

12. 2006–07 के लिए वार्शिक योजना 3300 करोड़ रूपए की थी, जबकि वास्तविक खर्च 4233 करोड़ रूपए था। वर्श 2007–08 के दौरान हमारी योजना का आकार 5300 करोड़ रूपए था और मुझे वि वास है कि वास्तविक योजनागत खर्च 5300 करोड़ रूपए में नही बल्कि 5900 करोड़ रूपए से भी अधिक होगा। इस प्रकार, हम अपनी योजना के आकार में साल दर साल वृद्धि कर रहे है। योजना आयोग ने 2008–09 के लिए 6650 करोड़ रूपये की योजना अनुमोदित की है। योजनागत खर्च, जो पिछली सरकार के भाासनकाल में लगभग 2000 करोड़ रूपयए का अटका हुआ था, अब केवल तीन वर्श में तीन गुणा से भी अधिक बढ़ गया है। गत तीन वर्श के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद में हमारी विकास दर ऊंची रही है और सकल राज्य घरेलू

उत्पाद में इस ऊंची विकास दर के बावजूद हमने यह सुनि चत किया है कि योजना के आकार और सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात, जो कम हो रहा था और जो 2004–05 में मात्र 2.25 प्रति ात के स्तर पर पहुंच गया था, को 2007–08 में 3.59 प्रति ात किया जाये और 2008–09 में इसे और बढ़ाकर 3.85 प्रति ात किया जायेगा। इस प्रकार हमारी योजनायें न केवल कुल रा ि ा की दृश्टि से बढ़ी हैं, बल्कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुसार की दृश्टि से भी बढ़ी है।

13. हमें अनुसूचित जातियों के अपने भाई–बहिनों, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों, महिलाओं और बच्चों के बारे में गहरी चिन्ता है। हालांकि अनुसूचित जातियों के लोगों की संख्या राज्य की कुल जनसंख्या का 19.35 प्रति ात है, तथापित हमने 20058–09 के दौरान योजनागत परिव्यय की 21. 65 प्रति ात रा ि ा अनुसूचित रा ि ा जातियों के वि ोश घटक उप–योजना (एस.सी.एस.पी.) के अन्तर्गत समाज के इस कमजोर वर्ग के कल्याण एवं विकास पर सीधे तौर पर खर्च करने के लिए निर्धारित की है। बी.पी.एल. और अनुसूचित जातियों के पात्र परिवारों को आवासीय प्लाट आबंटित करने की हमारी योजना है। लड़कियों के सामाजिक स्तर में वृद्धि करने की योजनाओं के अतिरिक्त हम ''जैंडर बजटिंग'' (Gender Budgeting) पर एक विवरण पत्र (Statement), जो 2008–09 के बजट दस्तावेजों के साथ संकल्प है, भी प्रस्तुत कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा

है। हमारी सरकार राज्य में समाज केन्द्रित विकास को बढ़ावा देने और विकास के लाभों को समाज के हर स्तर तक पहुंचाने के लिए वचनबद्ध है।

नई पहल

14. अध्यक्ष महोदय, अब मैं इस गरिमामय सदन में हमारी सरकार द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों के लाभ के लिए की गई और की जाने वाली नई भ्ाुरूआतों का विवरण प्रस्तुत करना चाहूंगा।

+ कृशि क्षेत्र की विकास दर समग्र रूप से धीमी पड़ गई है और अत्याधिक ग्रामीण कर्जदारी की वजह से हता ा व परे ाान किसानों द्वारा दे ा के कई भागों में आत्महत्याएं किए जाने की खबरें आईं।

हम इस अवसर पर यू.पी.ए. अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने 2008–09 के केन्द्रिय बजट में छोटे तथा सीमांत किसानों की कर्जदारी को प्रमुखता से उजागर करवाया है। भारत के वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम द्वारा बजट भाशण 2008–09 में समस्त दे ा के छोटे और सीमांत किसानों के बैंक ऋणों की माफी बारे की गई घोशणा अभूतपूर्व और साहसिक है और यह किसानों की कठिनाइयों को कम करने में काफी मददगार साबित होगी। इससे हमारे राज्य में भी बड़ी संख्या में किसान लाभान्वित होंगे और हम

इस ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम के लिए प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यू.पी.ए. सरकार का धन्यवाद करना चाहेंगे।

लेकिन हम यह भी मानते है कि बड़ी संख्या में ऐसे किसान भी है, जिन्होंने स्थानीय साहूकारें और आढ़तियों से बहुत ऊंची ब्याज दर पर ऋण ले रखा है। इस समस्या का भी तत्काल समाधान किए जाने की जरूरत है और साहूकारों के इस वर्ग को भी सरकार के प्र ाासनिक व वित्तीय नियंत्रण के दायरे में लाया जाना चाहिए। ऐसा करके ही इनकी गतिविधियों को समुचित रूप से नियंत्रित व विनियमित किया जा सकता है। हम भारत सरकार से आग्रह करेंगे कि वह इस सम्बन्ध में भीघ्राति ीघ्र उपचारात्मक उपाय करें।

+ पिछले बजट में, मैंने कम्पैक्ट फलोरेसैन्ट लैम्पस (सी.एफ.एल.), जो अब उपभोक्ताओं में लोकप्रिय हो रहे है, पर कर राहत की घोशणा की थी। इनसे बिजली का संरक्षण हो रहा है, जिसकी बहुत जरूरत है। वित्त वर्श 2008–09 से ऊर्जा की बचत करने वाली टयूबों के चोक्स पर भी यह कर राहत देने का मेरा इरादा है।

+ महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए सेनेटरी नैपकिनस, डायपरज और खिलौनों, जिनमें बैटरी चालित बिजली और इलैक्ट्रानिक्स के खिलौने भाामिल नहीं है, पर वैट समाप्त

करने का मेरा प्रस्ताव है। हम सेनेटरी नैपकिनस का उत्पादन करने वाली महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने पर भी विचार कर रहे है।

+ भूमि और सम्पत्ति की रजिस्ट्री पर लगने वले स्टॉम्प भाुल्क की दरें 2004 में कम करके भाहरी क्षेत्रों में आठ प्रति ात और ग्रामीण क्षेत्रों में 6 प्रति ात कर दी गई थी। सम्पत्ति की रजिस्ट्री महिला के नाम पर करवाये जाने पर हमने इन दरों पर दो प्रति ात की छूट दी थी। महिलाओं को दी गई इस छुट को जारी रखते हुए स्टॉम्प भाुल्क की दरों में एक प्रति ात की और कमी करने का मेरा इरादा है।

+ दिल्ली से गुड़गांव तक वाया महरौली मैट्रो रेल लिंक का विस्तार कार्य जोरों पर चल रहा है और इसकी जनवरी, 2010 तक पूरा होने की सम्भावना है। दिल्ली मैट्रो रेल निगम के बोर्ड ने मैट्रो रेल का विस्तार फरीदाबाद तक करने की अनुमति प्रदान कर दी है और बहादुरगढ़ तक इसके विस्तार का प्रस्ताव विचाराधीन है । इससे हमरे राज्य के एन.सी०आर० क्षेत्र का दिल्ली के साथ सम्पर्क सुगम होगा और इन जिलों से विकास गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा ।

हमारी सरकार सड़क एव परिवहन आधारभूत संरचना को अपग्रेड करके राज्य, विशेषज्ञ एन.सी.आर. की संयोजकता में से सुधार लाने तथा त्वरित परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने के

लिए हरियाणा सड़क एवं विकास निवास को गोडल एजेंसी नामजद करने पर विचार कर रही है ।

हमारा पी.जी.आई., रोहतक में एक हैड यूनिवर्सिटी (Health University) स्थापित करने का भी प्रस्ताव है । इसके गठन के लिये शीघ्र ही विधानसभा में एक विधेयक लाया जा रहा है। हमने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई.एस.आई.सी.) की वितीय सहायता से फरीदाबाद में एक नया स्नातकोत्तर सुविधाओं के साथ एक मेड़ीकल कॉलेज खोलने का भारत सरकार से आग्रह किया है। हमने इस उद्देश्य के लिये 25 एकड़ भूमि देने की पेशकश की है और ई.एस.आई. हास्पिटल, फरीदाबाद में पर्याप्त बिस्तर क्षमता उपलब्य है ।

अर्थ–व्यवस्था के विकास को सार्थक बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उसके लाभ कुछेक व्यक्तियों तह सीमित न रहकर समाज के सभी व्यक्तियों को बराबर रूप से मिलें। इस दिशा में हमने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 3510 रुपए कर दी है, जो देश से सर्वाधिक है ।

यहीं नहीं, हमने इस बजट में, सरकारी कर्मचारियों को भी लाम देने का प्रयास किया है, जैसा कि हमनैं अपने चुनावी घोषणा–पत्र में आश्वासन दिया था। कार ऋण की पात्रता, जो हाल ही मैं बढ़ाकर पांच लाख रुपए की गई थी, को बढ़ाकर छ़ लाख रुपए करने का प्रस्ताव है । इसी प्रकार, गृह ऋण की सीमा

7.5 लाख रूपए से 12.5 लाख रूपए और घर की मरम्मत तथा विस्तार के लिये ऋण सीमा वतर्मान में एक लाख रुपए और 1.80 लाख रुपए से बढ़ाकर क्रम ाः दो लाख रूपए और 2.5 लाख रूपए कर दी है । हमने गेहूं की खरीद के लिये दिये जाने वाले ब्याज ऋण का दायरा भी बढ़ा दिया है । इससे पहले यह ऋण केवल श्रेणी–डी के कर्मचारियों के लिये था। अब यह ऋण श्रेणी–सी के ऐसे कर्मचारियों को भी दिया जायेगा, जिनके मूल वेतन जमा महंगाई भत्ते की राशि 7000 रूपये प्रति माह हैं। यहीं नहीं, हमने छठे वेतन आयोजग की सिफारि ाों के फलस्वरूप वेतन तथा पें ान में होने वाली संभावित बढ़ोतरी के लिए भी वर्श 2008–09 के बजट में 1550 करोड़ रूपए की रा ि ा का प्रावधान किया है जिसकी रिपोर्ट अगले कुछ ही दिनों में आ जाएगी।

आज का युग ज्ञान–विज्ञान का है, जो अर्थ–व्यवस्था के प्रमुख संचालको से एक है । इसलिये विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों को अपने अनुसंधान कार्यों के स्तर में सुधार लाने के लिये कमर कसनी होगी । इस उद्दे य की प्राप्ति के लिए यह जरूरी है कि शिक्षको तथा वैज्ञानिकों को अंतर्राश्ट्रीय विचार–गोष्ठियों और सम्मेलनों में भाग लेने तथा अपने शोध–पत्र प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहन किया जाए। ऐसे भागीदारों के यात्रा खर्च की 50 प्रतिशत राशि सरकार द्वारा दिए जाने का प्रस्ताव है, जिसके लिए शिक्षा विभाग में एक कोश गठित किया जाएगा ।

शिक्षा सामाजिक बदलाव और समाज के कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है । समाज के कमजोर वर्गों, विशेषतः अनुसूचित जातियों के जिये सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने तथा उनका सामाजिक स्तर ऊंचा उठाने के लिये ''मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति शिक्षा प्रोत्साहन स्कीम'' नामकएक क्रांतिकारी योजना शुरु की गई है इस योजना से पढ़ाई अधूरी छोड़ने की दर, जो इन वर्गों के बच्चों में सबसे ज्यादा है, में कमी आयेगी । इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले अनुसूचित जातियों के सभी बच्चे को 100 रूपए से 300 रूपए प्रतिमास तक तथा सभी छात्रओं को 150 रूपए से 400 रुपए प्रतिमास तक छात्रवृत्यिां दी जायेंगी। अनुसूचित जातियों के सभी विद्यार्थियों को यूनिफार्म, लेखन सामग्री तथा स्कूल बैग इत्यादि के खर्च के लिए भी 740 रूपए से 1450 रूपये तक एक बारगी भत्ता दिया जाएगा। राज्य में बी.पी.एल. परिवारों की सभी छात्राओं को भी यह सुविधा देने का हमारा प्रस्ताव है।

हमारी सरकार ने जिला रिवाड़ी में राज्य का दूसरा सैनिक स्कूल खोजने का निर्णय लिया है, जिसके लिये ग्राम पंचायत गोठड़ा द्वारा भूमि उपलब्ध करवाई जा रही है । राज्य सरकार आधारभूत ढ़ाचे के निर्माण के लिये आवश्यक पूंजी उपलबय करवायेगी और स्कूल चलाने के लिये अनुदान भी देगी ।

शहरी स्थानीय निकायों के संसाधनो में वृद्धि करने के लिये उन्हें अपने क्षेत्राधिकार से विज्ञापन अधिकार नीलाम करने

और बिजली के खम्बों का प्रयोग करने वाले केबल आप्रेटरों पर प्रयोगकर्ता शुल्क लगाने के लिये प्राधिकृत किया जायेगा। शहरीं स्थानीय निकायों को ये अधिकार भी दिये जायेगे कि वे उन केबल ऑप्रेटरों पर अधिभार लगायें जो अपने केबल नैटवर्क पर वाणिज्यिक विज्ञापन दिखाते है।

हमने पंजीकृत बेरोजगार विज्ञान स्नातकों और स्नातकोत्तर को 50 प्रति ात अधिक बेरोजगारी भत्ता देने का निर्णय लिया है। इसी प्रकार, राज्य के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत सभी बेरोजगार महिलाओं को भी पुरूशों की अपेक्षा 50 प्रतिशत अधिक बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा ।

सरकार कृशि पम्प सैटों को सस्ती बिजली सप्लाई करने के लिए बिजली निगमों को सबसिडी प्रदान कर रही है। आर.ई. सबसीडी, जो 2004–08 में 1102 करोड़ रूपए थी, वर्श 2006–07 में बढ़कर 1544 करोड़ रूपए हो गई और जिसकी वर्श 2007–6 में लगभग 2366 करोड़ रूपए हो जाने की सम्भावना है। बढ़ती हुई सबसिडी सरकार के लिए एक चिन्ता की बात है और हम किसानों के लाभार्थ ग्रामीण विद्युत सबसिडी को बेहतर ढंग से लक्षित करने पर विचार कर रहे है। जिसको डारेक्ट सबसिडी भी आप कह सकते है।

सरकार अनुसूचित जातियों के लाभानुभोगियों को मकानों के निर्माण के लिए 50,000 रूपए की सबसिडी दे रही है।

निर्माण की बढ़ती हुई लागत के दृश्टिगत इन लोगों को इस सबसिडी की रा ि ा से अपना मकान पूरा करने में कठिनाइयां महसूस हो रही है और वे अपने संसाधनों से भी इस उद्दे य के लिए अतिरिक्त धन जुटाने में सक्षम नहीं है। हमारी सरकार ने एक नई योजना भ्ारू करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत अनुसूचित जातियों के सदस्यों को मकानों के निर्माण के लिए कम ब्याज दर पर ऋण दिया जायेगा। हम इस कार्य में वाणिज्यिक बैंकों को भी भ्ामिल करने का प्रयास करेंगे।

15. अध्यक्ष महोदय, अब मैं, वर्श 2008–09 में महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए किए गए बजट आबंटन प्रस्तुत करता हूं।

बिजली

16. हमारी सरकार बिजली क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं इस समय राज्य की बिजली उत्पादन क्षमता 4368 मैगावाट है और उपभोक्ताओं को प्रतिदिन औसतन 739 लाख यूनिट बिजली की जा रही है। आगामी पांच वर्श में बिजली की मांग बढ़कर दुगुनी हो जाने की सम्भावना है। सभी उपभोक्ताओं को पर्याप्त मात्रा में उच्च कोटि की बिजली सप्लाई करना हमारी विकास नीति की अपेक्षा है। इस उद्दे य की पूर्ति के लिए सरकार ने सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए नई पहल की है।

11वीं पंचवर्शीय योजना के दोरान नये बिजली उत्पादन संयंत्रों और सम्प्रेषण व वितरण प्रणालियों के सुदृढीकरण पर 24,317 करोड़ रूपए का निवेश करने का प्रस्ताव है । राज्य सरकार योजना कोष से 20 प्रतिशत इक्विटी उपलब्ध करवायेगी, और शेष 80 प्रति ात रा ि ा बिजली निगमों द्वारा वित्तीय संस्थानों से ऋण के रूप से जुटाई जायेगी। हमारी योजना वर्ष 2011 तक बिजली की प्रस्तापित क्षमता में 5000 मेगावाट की वृद्धि करने की है, जो वर्ममान क्षमता से दुगुनी से भी अधिक है । हमें आशा है कि इससे मांग और आूपर्ति का अन्तर समान हो जायेगा । इसके अलावा, 11वीं योजना के दोरान 1148 मैगावाट अतिरिक्त बिजली उपलब्ध करवाने के लिए स्वतंत्र बिजली उत्पादकों तथा केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं से बिजली खरीद समझौते किए गए है।

18. यमुनानगर से स्थापित की जा रहीं 300–300 मेगावाट की दो इकाइयों से से पहली इकाई को नवम्बर, 2007 में सिंक्रोनाईज (Synchronize) किया गया तथा दूसरी इकाई को इसी कोने से सिंक्रोनाईज (Synchronize) किये जाने की सम्भावना है । हिसार के खेदड़ में 1200 मेगावाट के कोयला आधारित 'राजीव गांधी थर्मल प्लांट' पर भी कार्य शुरू किया जा चुका है और इस प्लांट को वर्ष 2009–10 से चालू किए जाने का लक्ष्य है । हरियाणा सरकार, दिल्ली सरकार तथा राश्ट्री ताप बिजली निगम द्वारा संयुक्त रूप से जिला झज्जर में 1500 मैंगावाट क्षमता का

कोयला आधारित एक और थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है । यह प्लांट वर्ष 2010 में चालू होगा तथा इससे हरियाणा को 750 मेगावाट बिजली मिलेगी। शुष्क आधारित बोली प्रक्रिया के माध्यम से मातनहेल में 1150 मेगावाट क्षमता का एक और संयत्र लगाने का प्रस्ताव है ।

19. अक्षय उर्जा नीति के तहत हरेडा ने 697.7 मेगावाट क्षमता की 23 बोया–मास (Bio-Mass) तीन लघु पन बिजली तथा चार पवन बिजली परियोजना स्थापित करने के लिए स्वतंत्र बिजली उत्पादकों से समझौते किए है। बोया–मास (Bio-Mass) संयत्रों के मामले से, 75 मेगावाट की सात विस्तृत परियोजना रिपोर्ट स्वीकृत की जा चुकी हैं, किया जाएगा है दस मेगावाट की परियोजना की स्थापना के लिए एक स्थल आबंटित किया गया है तथा इस सम्बन्ध में सम्बन्ध में 4.7 अनिल की लघु पन बिजली परियोजनाओं की तीन विस्तृत परियोजना रिपोर्ट स्वीकृत की जा चुका हैं तजा एक स्वर्ण पर निक कारों शूल भी हो चुका है। इसी प्रकार 340 मेगावाट की पवन बिजली परियोजनाओं की तीन विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अप्रैल 2008 में प्रस्तुत की जाएगी तथा सर्वोच्च न्यायालय की रोक के कारण एक मामले में प्रक्रिया अभी शुरु की जानी है ।

20. 130 मैंगावाट बिजली उत्पन्न करने के लिए प्रदेश की सभी चीनी मिलों से हाई प्रेशर बायलर्ज एव टर्बाइन्ज, (High Pressure Boilers and Turbines) के साथ बिजली सह–उत्पादन

संयंत्र स्थापित करने की भी हमारी योजना है जिसमें से 85 मैगावाट बिजली राज्य बिजली ग्रिड को मिलेगी ।

11.00 बजे

21. हमारी सरकार सतत विकास के लिए उस संरक्षण में विश्वास रखती है। इसी के मद्देनजर वितरण कम्पनियां उर्जा की बचत करने वाले उपकरणों के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। अव तक हरियाणा के 650 गांवों, में काम्पैक्ट फ्लोरोसैंट (Compact Fluorescent Lamps) लगाए जा चुके है । शहरी क्षेत्रों में भी काम्पैक्ट फ्लोरोसैंट (Compact Fluorescent Lamps) के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हरियाणा के लोग इनके लाभ को समझने लगे है । इससे लोगों को वित्तीय लाभ हुआ है और प्रदे ा में उर्जा की बचत हुई है।

22. बिजली वितरण में सुधार के लिए कृशि फीडरों को अलग करने, उच्च वोल्अेज वितरण प्रणाली भुरू करने, कण्डक्टर क्षमता को बढ़ाने, उपभोक्ता मीटरों को दूसरी जगह लगाने जैसे अनेक कार्य प्रगति पर है। 11वीं योजना मे ंसम्प्रेशण प्रणाली के उन्नयन पर 7698 करोड़ रूपए तथा वितरण तंत्र को सुदृढ़ करने पर 6577 करोड़ रूपए खर्च किए जाएंगे। गत तीन वर्शों में 68 नए सब–स्टे ान स्थापित किए गए 182 सब–स्टे ानों की क्षमता बढ़ाई गई 37386 अतिरिक्त वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित

किए गए और 1138 किलोमीटर लंबी नई सम्प्रेशण लाइनें बिछाई गई।

23. वर्श 2008–09 में, बिजली क्षेत्र के लिए अक्षय ऊर्जा समेत योजनागत तथा योजनेतर 3528.88 करोड़ रूपए की राि ा रखी गई है, जबकि 2007–08 में यह 3149.88 करोड़ रूपए थी।

सिंचाई

24. प्रदे ा भर में पानी का समान वितरण सुनि चत करना हमारा चुनावी वादा था और हमने उस वादे को पूरा किया है। इस वोद को पूरा करने के लिए हमारी सरकार ने भाखड़ा मेन लाईन को हांसी–बुटाना ब्रांच से जोड़ने के लिए 109 किलोमीटर लंबी बहु–उद्दे ीय सम्पर्क नहर का निर्माण भारू किया, जिसके चालू वित्त वर्श में पूरा होने की सम्भावना है। इस नहर के पूरा होने के बाद मेवात के पिछड़े क्षेत्रों में सिंचाई एवं पेयजल सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए एक नहर का निर्माण प्रस्तावित है। जवाहर लाल नेहरू फीडर की क्षमता 1500–1600 क्यूसिक से बढ़ाकर 2200 क्यूसिक की गई है तथा इस क्षमता को 2500 क्यूसिक तक और बढ़ाया जा रहा है।

26. औद्योगिक भाहर, गुड़गांव, मानेसर, बहादुरगढ़ एवं खरखौदा की भावी मांग को पूरा करने के लिए राश्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जलापूर्ति चैनल का निर्माण कार्य भारू किया गया है, जिसके

वर्श 2008–09 के दौरान पूरा होने की सम्भावना है। कृशि भूमि एवं ग्रामीण आबादी को बाढ़ के प्रकोप से बचाने के लिए बाढ़ नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्वीकृत योजनाओं के अनुसार वर्श 2008–09 में लगभग 100 करोड़ रूपये खर्च किए जाएगें।

27. वर्श 2008–09 के दौरान, बाढ़ नियंत्रण तथा भाहरी क्षेत्र विकास प्राधिकारण समेत सिंचाई के लिए योजनागत तथा योजनेतर 1477.21 करोड़ रूपए की रा ि ा आबंटित की गई है, जबकि 2007–08 में 1373.66 करोड़ रूपए की रा ि ा आबंटित की गई थी।

28. हालांकि 31 मार्च 1992 तक प्रदे ा के सभी गांवों में पेयजल सुविधा पहुंचाई जा चुकी थी, तथापि कई गांवों में पानी की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कम है। हमने वर्श 2006–07 में पेयजल की कमी वाले 1103 गांवों की जलापूर्ति में वृद्धि की है तथा वर्श 2007–08 में 500 और गांवों में वृद्धि होने की सम्भावना है। भोश गांवों में वर्श 2008–09 में जल संवृद्धि का कार्य किया जाएगा।

29. इन्दिरा गांधी पेयजल योजना के तहत अनुसूचित जाति के परिवारों को निः ाुल्क व्यक्तिगत पेयजल कनैक ान दिए जा रहे है। वर्श 2007–08 के दौरान इस योजना के तहत 3.30 लाख परिवारों को कनैक ान देने की सम्भावना है तथा भोश परिवारों को वर्श 2008–09 तथा 2009–10 में कनैक ान दिए

जाएंगे। अनुसूचित जाति के परिवारों को पानी के मासिक भुल्क की अदायगी मं 50 प्रति ात की छूट भी दी जा रही है। सामान्य वर्ग के परिवारों को पानी के निजी कनैक ान लेने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्दे य से गांवों में 500 रूपए तथा भाहरी क्षेत्रों में 1000 रूपए की कनैक ान फीस समाप्त कर दी गई है।

30. मेवात क्षेत्र में सतत पेयजल आपूर्ति सुनि चित करने के लिए राश्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की वित्तीय सहायता से 205.91 करोड़ रूपए की लागत से एक महत्वाकांक्षी राजीव गांधी संवर्धन पेयजल परियोजना पर कार्य प्रगति पर है। इस परियोजना के तहत यमुना नदी के मैदानी क्षेत्र में तीन रैनी वैल्ज का निर्माण किया जाएगा तथा उपयुक्त स्थानों पर स्थापित बूस्टिंग केन्द्रों वाले वितरण तंत्र के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जाएगी। इसके अलावा, जून 2008 तक 290 नलकूप लगाने का कार्य पूरा किया जाएगा, जिससे 503 मेवात के गांव लाभान्वित होंगे।

31. प्रदे ा के सभी भाहरों में पाईप्स के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है। राश्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वर्तमान जलापूर्ति एवं सीवरेज आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के लिए राश्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा एन.सी.आर. के भाहरों तथा 'काऊंटर मैगनेट' भाहर हिसार के लिए भी ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है।

32. वर्श 2008–09 मैं, पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता क्षेत्र के लिए योजनागत तथा योजनेतर 1237.44 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है, जबकि 2007–08 में इस क्षेत्र के लिए 1120.44 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

सड़कं एवं पूल

हमारी सरकार सडत्रकों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। सरकार ने 3000 करोड़ रूपए के निवे ा का राजीव गांधी पुल एवं सड़क आधारभूत संरचना विकास कार्यक्रम भ्रारू किया है, जो तीन चरणों में पूरा होगा। इस कार्यक्रम के प्रथम चरण के तहत 1000 करोड़ रूपए की लागत की परियोजनाएं पहले ही भ्रारू हो चुकी है। इस कार्यक्रम के लिए राज्य के संसाधनों के अलावा भारत सरकार तथा अन्य वित्तीय एजेंसियों से धन जुटाया गया है। वर्श 2007–08 के दौरान 3200 किलोमीटर लंबी सड़कों को सुधारा गया है। वर्श 2008–09 के दौरान 4500 किलोमीटर लंबी सड़कों को सुधारा जाना प्रस्तावित है।

50. जवाहर लाल नेहरू राश्ट्रीय भाहरी नवीकरण मि ान के अन्तर्गत फरीदाबाद में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 1203.59 करोड़ रूपए की सात विस्तृत परियोजना रिपोर्टस भारत सरकार को प्रस्तुत की गई है। इसमें से 275.33 करोड़ रूपए की रा ि ा स्वीकृत की जा चुकी है और 21.39 करोड़ रूपए की रा ि ा

प्राप्त हो चुकी है। अब पंचकूला को भी चण्डीगढ़ और मोहाली के साथ ट्राई–सिटी के रूप में जवाहर लाल नेहरू राश्ट्रीय भाहरी नवीकरण मि ान में भाामिल किया गया है। सड़क, जल निकासी, जलापूर्ति एवं सीवरेज जैसी आधारभूत संरचनाओं की कमी को पूरा करने के लिए हरियाणा के 73 भाहरों के लिए नगर विकास योजनाएं तैयार की गई है। पंचकूला भाहर के लिए एक विकास योजना तैयार करने का कार्य भाुरू किया गया है।

51. छोटे एवं मध्यम भाहरों के लिए भाहरी आधारभूत संरचना विकास योजना के तहत रोहतक, करनाल, इन्द्री, यमुनानगर एवं जगाधरी की समेकित ठोस कचरा प्रबन्धन हेतु चार विस्तृत परियोजनाओं तथा बहादुगढ़ में 100.96 करोड़ रूपए की लागत से बनने वाली सीवरेज प्रणाली एवं सीवेज उपचार प्लांट की परियोजना स्वीकृति व धनरा ि जारी करने हेतु भारत सरकार को प्रस्तुत की गई है।

52. नगर एवं आयोजना विभाग समेत भाहरी विकास क्षेत्र का योजनागत तथा योजनेतर कुल आबंटन वर्श 2007–08 में 269.56 करोड़ रूपए के मुकाबले वर्श 2008–09 में 399.98 करोड़ रूपए किया गया है।

ि ाक्षा एवं खेल

53. ि ाक्षा हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ि ाक्षा के लिए बजट आबंटन को वर्श 2004–05 में 1450 करोड़

रूपए से बढ़ाकर वर्श 2007–08 में 2732.92 करोड़ रूपए किया गया। वर्श 2008–09 में ि ाक्षा के लिए 3139.08 करोड़ रूपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

54. स्कूली पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने वाले विद्यार्थियों की दर को कम करना हमारी सर्वोच्य प्राथमिकता है। पहली से आठवीं कक्षा में पढ़ रहे विद्यार्थियों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें और वर्कबुक्स उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया है। ि ाक्षा के स्तर को सुधारने के एिल वर्कबुक्स, परियोजना आधारित अध्ययन तथा सामान्य ज्ञान का विशय भ्ारू किया जा रहा है। ि ाक्षकों की गुणवत्ता सुधारने के लिए भी नीतिगत निर्णय लिये जा रहे है।

55. वरिश्ठ माध्यमिक स्कूलों के विद्यार्थीयों के लिए कम्प्यूटर ि ाक्षा को चरणबद्ध ढंग से अनिवार्य बनाया जा रहा है। प्रथम चरण में 200 बड़े वरिश्ठ माध्यमिक स्कूलों के लिए पूर्णतः सुसज्जित कम्प्यूटर प्रयोग ाालाओं, रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम तथा योग्य ि ाक्षकों की व्यवस्था की जा रही है।योजनागत संसाधनों की मदद से तथा भारत सरकार की योजनाओं के तहत प्रदे ा के स्कूल तंत्र का उन्नयन किया जाएगा।

56. प्रदे ा में उच्चतर ि ाक्षा को भी पूर्णतः नया रूप दिया जाना प्रस्तावित हैं आगामी भौक्षणिक सत्र से सरकारी एवं निजी कालेजों में बी.बी.ए., बी.सी.ए., बी कॉम जैसे रोजगारोन्मुखी

पाठ्यक्रमों में बहुत बड़ी संख्या में सीटें उपलब्ध करवाई जाएंगी। कालेज के विद्यार्थियों के लिए भी कम्प्यूटर ि ाक्षा को अनिवार्य किया जा रहा है। भाुरू में, आगामी वित्त वर्श से 25 बड़े कालेजों में इसे अनिवार्य किया जाएगा। विज्ञान, अर्थ ाास्त्र तथा वाणिज्य संबंधी पाठ्यक्रमों में सीटों की संख्या बढ़ाकर वि वविद्यालयों को सुदृढ़ किया जा रहा है। कालेजों में सैमेस्टर प्रणाली भाुरू किया जाना भी प्रस्तावित है।

57. चालू वित्त वर्श के दौरान एजुसैट (Edusat) तंत्र का विस्तार किया गया और इसे आगे और सुदृढ़ किया जाएगा। पहीले से ही विद्यालय में भाुरू की गई समैस्टर प्रणाली में भी सुधार लाये गए है।

58. वर्श 2006 में दोहा (कतर) में आयोजित 15वें एि ायाई खेलों में प्रदे ा के 23 खिलाड़ियों ने पदक जीते। इन खिलाड़ियों को 148 लाख रूपए के नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। 28 नवम्बर, 2007 से 2 दिसम्बर, 2007 तक कोलकाता में आयोजित 12वीं एि ायाई महिला रोल्लर स्कैटिंग हॉकी टूर्नामैंट में भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इस टीम में प्रदे ा के आठ खिलाड़ी थे, जिन्हें एक–एक लाख रूपए का नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

59. मोती लाल नेहरू खेल विद्यालय, राई में 3.45 करोड़ रूपए की लागत से एक अन्तर्राश्ट्रीय स्तर का सैन्थेटिक

हॉकी ग्रास सरफेस (Synthetic Hockey Grass Surface) (Astroturf) बिछाया जा रहा है। खिलाड़ियों के खुराक भत्ते में पर्याप्त वृद्धि करने का भी हमारा इरादा है। हम ग्रामीण विद्यार्थियों को खेलों के लिए प्रोत्साहित करने हेतु अनेक गांवों में ग्रामीण खेल स्टेडियमों का भी निर्माण करवा रहे है।

स्वास्थ्य सेवाएं

60. प्रदे ा में 50 अस्पतालों, 65 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 420 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 2433 उपकेन्द्रों, 20 जिला टी.बी. सैंटरों, 41 औशधालयों, पंडित भगवत दयाल भार्मा स्नातकोत्तर चिकित्सा ि ाक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, रोहतक और चिकित्सा महाविद्यालय, अग्रोहा (हिसार) और मुलाना (अम्बाला) के नेटवर्क से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही है।

61. ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसूति गृहों के माध्यम से संस्थागत प्रसूति की सेवाएं उपलब्ध होने से ि ा ु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में कमी आई है, जोकि एक उत्साहवर्धक परिणाम हैं सुरक्षित प्रसव सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए 475 प्रसूति गृह स्थापित किये जा चुके है। वर्श 2008–09 के दौरान ऐसे 500 और प्रसूति गृह स्थापित करने का प्रस्ताव है।

62. जिला मेवात में गर्भवती महिलाओं को नजदीकी स्वास्थ्य संस्थान में ले जाने के लिए 2 अक्तूबर से 9 एम्बुलैंस उपलब्ध करवाकर मोबाइल स्वास्थ्य सेवाएं आरम्भर की गई ह।

एम्बुलैंस के चालकों को मोबाइल फोन दिये गये हैं ताकि समय पर उनकी उपलब्धता सुनिि चत की जा सके। राज्य के मोरनी (पंचकूला) जैसे अन्य दुर्गम क्षेत्रों में इसी प्रकार की योजना भाुरू करने का प्रस्ताव है।

65. आयूश और चिकित्सा ि ाक्षा समेत स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण क्षेत्र का योजनागत व योजनेतर आबंटन वर्श 2007–08 में 581.60 करोड़ रूपए के मुकाबले वर्श 2008–09 में 684.04 करोड़ रूपए किया गया है।

कमजोर वर्ग का कल्याण

66. हरियाणा सरकार समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण के प्रति वचनबद्ध है। सरकार ने वृद्धों, विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, विकलांगों, किनरों, बोनो, अल्पसंख्यकों और ऐसे परिवारों, जिनमें केवल लड़कियां हैं, को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अनेक प्रभावी कदम उठाये है।

67. हरियाणा सरकार ने अप्राकृतिक कारणों से मृत्यु या स्थाई रूप से विकलांग होने की स्थिति में हरियाणा के 18 से 60 वर्श की आयु वर्ग के सभी पात्र व्यक्तियों को राजीव गांधी परिवार बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है।

68. राज्य सरकार का स्कूलों में न जाने वाले विकलांग बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वर्श 2008–09 से एक नई स्कीम भाुरू करने का प्रस्ताव है। पहले यह कहते थे कि 18 वर्श से कम को यह सुविधा नहीं मिलेगी। मगर इस स्कीम के तहत 40 प्रति ात या इससे अधिक की विकलांगता वाले 6 से 18 वर्श की आयु वर्ग के बच्चों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी।

69. हरियाणा सरकार ने प्रदे ा की सभी भाहरी सम्पदाओं में वृद्धों के लिए 'डे–केयर सैंटर्ज' (Day Care Centres) स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। इन केन्द्रों ने वरिश्ट नागरिकों को इन्डोर खेलों, जल–पान, पुस्तकालय, वाचनालयों, चिकित्सा इत्यादि की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी।

70. अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक–आर्थिक उत्थान तथा उनके भौक्षणिक स्तर में सुधार लाने हेतु उन्हें विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने चालू वित्त वर्श से ही छात्रवृत्रि, निः ाुल्क कोचिंग इतयादि की भात–प्रति ात केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं क्रियान्वित करने का निर्णय लिया है। सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों द्वारा बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर में कमी लाने के लिए केन्द्र की हिस्सेदारी से पूर्व मैट्रिीक छात्रवृत्ति की एक योजना क्रियान्वित करने का भी निर्णय लिया है।

71. अनुसूचित जातियों के मेधावी विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए वर्श 2005–06 से 'डॉ. अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना' भ्ारू की गई थी। बहुतकनीकि संस्थानों और औद्योगिक प्र ि ाक्षण संस्थाओं में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों को भी वर्श 2007–08 से इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृति प्राप्त करने के लिए पात्र बनाया गया है। वर्श 2008–09 के दौरान अनुसूचित जातियों के और अधिक विद्यार्थियों को इस स्कीम में भ्ामिल करने का भी हमारा प्रस्ताव है। अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए उत्कृश्ट कार्य करने वाली पंचायतों को दी जा रही प्रोत्साहन रा ि ा में दस गुणा वृद्धि करते हुए 5,000 रूपए से बढ़ाकर 50000 रूपए कर दी गई है।

महिला एवं बाल विकास

72. हम महिलाओं और बच्चों के विकास और उनके स्तर में सुधार के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित कर रहे हैं। घटता लिंगानुपात एक बड़ी चिंता का विशय है। वर्श 2005–06 में भ्ारू की गई लाडली योजना हमारी सरकार द्वारा इस संदर्भ में उठाये गये महत्वपूर्ण कदमों में से एक है, जिसके उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हो रहे है। बच्चों, वि ोशकर 6 वर्श से कम आयु के बचों में रक्त की कमी और कुपोशण की समस्या के समाधान के लिए वर्श 2008–09 से एक वि ोश स्कीम भ्ारू की जा रही है। इस स्कीम के तहत उनके आधार में पोशक तत्वों, फोलिक एसिड तथा विटामिन 'ए' की वृद्धि की जाएगी और उन्हें कृशि

ना ाक दवाई पिलाई जाएगी। सरकार द्वारा भाुरू की गई विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कमजोर वर्गों को बेहतर सेवाए ंप्रदान करने के लिए अनुसूतिच जातियों की बस्तियों के अथवा उनके निकट आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है।

73. वर्श 2007–08 में राज्य सरकार द्वारा उठाये गये अन्य प्रमुख कदमों में महिलाओं एवं बच्चों से सम्बन्धित मामलों पर उचित कार्यवाही करने के लिए ग्राम पंचायत की एक उप–समिति के रू॰ में कार्य करने के लिए ग्राम स्तरीय समितियों का गठन करना भाामिल है। लगभग 6500 ग्राम स्तरीय समितियों ने कार्य आरम्भ कर दिया है और इन समितियों ने आंगनवाड़ी केन्द्रों के लााभापात्रों के लिए स्वयं सहायता सममूहों के माध्यम से पूरक पोशाहार उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण कार्य आरम्भ कर दिया है। इस व्यवस्था ने लगभग एक लाख महिलाओं को निर्णय लेने की अहम् भमिका में भाामिल कर दिया है। ि ाक्षित महिलाओं के 6000 से अधिक साक्षर महिला समूह, जो सोसायटी के रूप में पंजीकृत है, गठित किये गये है, जो गांवों में सामाजिक बदलाव लाने और विकास करने के लिए गैर सरकारीसंगठनों की तरह कार्य करेंगे।

74. अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों, सामाजिक न्याय एवं अधिकृारिता, महिला एवं बाल विकास तथा पोशाहार समेत समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए वर्श 2008–09

में योजनागत तथा योजनेतर 1264.24 करोड़ रूपए की रा ि ा रखी गई है जबकि 2007–08 में यह 1125.56 करोड़ रूपए थी।

औद्योगिक प्र ि ाक्षण एवं तकनीकी ि ाक्षा

75. प्रदे ा में तीव्र औद्योगिकीकरण के कारण तकनीकी मानव ाक्ति की मांग तेजी से बढ़ रही है। रोजगार के नये अवसरों का लाभ उठाने के लिए हमारी सरकार तकनीकी ि ाक्षा के विस्तार और औद्योगिगक प्र ि ाक्षण संस्थानों सहित 195 औद्योगिक प्र ि ाक्षण संस्थानों द्वारा औद्योगिक प्र ि ाक्षण प्रदान किया जा रहा है। आगामी तीन वर्शों के दौरान प्रदे ा में 31 नए औद्योगिक प्र ि ाक्षण संस्थान खोलने का प्रस्ताव है, जबकि वर्श 2008–09 के दौरान छः औद्योगिक प्र ि ाक्षण संस्थानों का विस्तार किये जाने और सात एस.सी. विंग (S.C. Wing) भ्ारू किये जाने का विचार है।

76. इस समय, हरियाणा राज्य में दो तकनीकी वि वविद्यालय, 61 इंजीनियरिंग महाविद्यालय, 90 एस.सी.ए./एम. बी.ए. महाविद्यालय/वि वविद्यालय विभाग, 27 फार्मेसी महाविद्यालय/वि वविद्यालय विभाग, तीन होटल प्रबन्धन महाविद्यालय तथा 76 बहुतकनीकी संस्थान है। छोटू राम राज्य इंजीनियरिंग कालेज, मुरथल का दर्जा बढ़ाकर इसे दीन बन्धु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वि वविद्यालय बना दिया गया है।

77. वर्श 2008–09 के दौरान सांपला और मोरनी में दो नये बहुतकनीकी संस्थान खोलने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, पबनावा 2008–09 के दौरान सांपला और मोरनी में दो नये बहुतकनीकी संस्थान खोलने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, पबनावा (कैथल), उमरी (कुरूक्षेत्र) और दामलावास (रेवाड़ी) में सार्वजनिक निजी भागीदारी से नये संस्थान खोलने का विचार है। रोहतक के फै ान एण्ड डिजाईन (Fashion and Design), ललित कला (Fine Arts), फिल्म एण्ड टी.वी. प्रोफै ान स्टडीज (Film and TV Professional Studies) के नये संस्थान आरम्भ किए जा रहे है। राजकीय बहुतकनीकी संस्थानों में फै ान डिजाईन (Fashion Design)] आन्तरिक साज सज्जा (Interior) है। छोटू राम राज्य इंजीनियरिंग कालेज, मुरथल का दर्जा बढ़ाकर इसे दीन बन्धु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वि वविद्यालय बना दिया गया है।

78. तकनीकी ि ाक्षा विभाग ने कागज रहित दाखिलों के लिए भारत सरकार से ''ई भाासन 2007–09 के लिए गोल्डन आइकन अवार्ड'' प्राप्त किया है।

79. औद्योगिक प्र ि ाक्षण एवं तकनीकी ि ाक्षा के लिए योजनागत तथा योजनेतर आबंटन वर्श 2007–08 के कुल 291.22 करोड़ रूपए के मुकाबले वर्श 2008–09 में 351.32 करोड़ रूपए किया गया है।

उद्योग

80. वर्श 2005 में हमारी सरकार के सता सम्भालने के बाद प्रदे ा में लगभग 33000 करोड़ रूपए का अभूतपूर्व निवे ा हुआ है और 66000 करोड़ रूपए से अधिक के निवे ा की परियोजनाएं विचाराधीन है। अब तक प्रदे ा में 10500 करोड़ रूपए का विदे ाी प्रत्यक्ष निवे ा प्राप्त हुआ है, जिसमें से 7000 करोड़ रूपए का विदे ाी प्रत्यक्ष निवे ा नई औद्योगिक नीति 2005 लागू होने के बाद आया है।

81. राज्य को वि ोश आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए 22 प्रस्ताव प्राप्त हुए है, जिनमें दो लाख करोड़ रूपए से अधिक निवे ा होगा और 20 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। केन्द्र सरकार द्वारा 51 प्रस्तावों को सैद्धान्तिक/औपचारिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इस वर्श दिसम्बर 2007 तक 33762 करोड़ रूपए के निवे ा के 27 वि ोश आर्थिक क्षेत्रों के प्रस्ताव प्राप्त हुए है, जिनमें चार लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने की क्षमता है।

82. राज्य सरकार प्रदे ा में आधारभूत संरचना परियोजनाओं के सार्वजनिक निजी भागीदारी तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन देने की नीति को जारी रखेगी। राज्य के सर्वांगीण औद्योगिक विकास और रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित करने के लिए हमारी नीतियां ऐसी बड़ी–बड़ी परियोजनाओं पर केन्द्रित रहेंगी, जो दूसरे कई उद्योगों के विकास में सहायत होंगी। कृशि आधारित खाद्य प्रसंस्करण

उद्योग को बढ़ावा देने की हमारी प्राथमिकता होगी। इसके अतिरिक्त, सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, वस्त्र, वैज्ञानिक उपकरणों, आटोमोबाईज्ल एवं आटो कम्पोनैंटस इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

83. वर्श 2008–09 में, उद्योग विभाग के लिए योजनागत तथा योजनेतर कुल 231.52 करोड़ रूपए की रा ि ा का प्रावधान किया गया है, जबकि पिछले वर्श 2007–08 में 89.99 करोड़ रूपए का प्रावधान है।

84. उद्योगों की सुविधा के लिए कारखाना अधिनियम 1948 और अनुबंध श्रमिक (आर एण्ड ए) अधिनियम 1970 के अन्तर्गत पंजीकरण और लाईसैंस प्रदान करने की भाक्तियां क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रदान की गई है। अनुबंध श्रम अधिनियत के अंतर्गत सभी श्रम उपायुक्तों को अपने–अपने क्षेत्रों में पंजीकरण एवं लाईसैंस अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है।

85. श्रमिकों को भीघ्र न्याय प्रदान करने के लिए प्रदे ा में नौ औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम अदालतें कार्य कर रही है। इसके अतिरिक्त, काफी समय से लंबित मामलों के निपटान के लिए लोक अदालतों का भी आयोजन किया जा रहा है। प्रदे ा में अकु ाल श्रमिक का न्यूनतम वेतन पहली जुलाई, 2007 से सं ाोधित करके 3510 रूपए प्रति माह किया गया है और श्रमिक श्रेणी से संबन्धित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में होने

वाली वृद्धि को बेअसर करने के लिए हर छः महीने में इसे अपडेट किया जाएगा।

86. राश्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जो पहली अप्रैल, 2008 से चार जिलों के लिए स्वीकृत की गई है, के अन्तर्गत बी. पी.एल. परिवारों का 30000 रूपए तक का बीमा किया जाएगा। वर्श 2008–09 के दौरान इस योजना के अंतर्गत चार और जिलों को भाामिल किये जाने की सम्भावना है। प्रीमियम रा ि ा का खर्च केन्द्र सरकार और राज्य सरकार 75:25 के अनुपात में वहन करेंगी। बीमाकृत परिवारों को स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएगें और यह लेन–देन नकदी रहित और कागज रहित होगा।

87. वर्श 2008–09 के दौरान श्रम एवं रोजगार विभाग के लिए योजनागत तथा योजनेतर 33.41 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

बजट अनुमान 2008–09

88. अध्यक्ष महोदय, अब मैं इस गरिमामय सदन के सम्मुख वर्श 2008–09 के बजट अनुमान प्रस्तुत करता हूं।

89. जैसा कि मैंने अपने अभिभाशण के आरम्भ में कहा है कि वर्श 2008–09 की वार्शिक योजना के लिए 6650 करोड़ रूपए का आबंटन प्रस्तावित है। बिजली क्षेत्र को 867 करोड़ रूपए, सिंचाई क्षेत्र को 790 करोड़ रूपए, जलापूर्ति एवं स्वच्छता को 653 करोड़ रूपए तथा सड़क एवं परिवहन क्षेत्र को 766 करोड़ रूपए

मिलेंगे। सामाजिक क्षेत्र के अन्य कार्यक्रमों के लिए आंबटन 2476 करोड़ रूप्ए होगा, जिसमें औद्योगिक प्र ि ाक्षण एवं तकनीकी ि ाक्षा सहित ि ाक्षा के लिए 970 करोड़ रूपए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के लिए 640 करोड़ रूपए, पोशाहार समेत महिला एवं बाल विका के लिए 172 करोड़ रूपए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 164 करोड़ रूपए तथा अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए 130 करोड़ रूपए भाामिल है।

90. वर्श 2007–08 भारतीय रिजर्व बैंक के खातों के अनुसार 12.58 करोड़ रूप्ए के अधि ोश के साथ भाुरू हुआ और 3.80 करोड़ रूपए के अधि ोश के साथ समाप्त होने की सम्भावना है। वर्श का लेन–देन 8.78 करोड़ रूपए की कमी द ार्ाता है।

91. वित्त वर्श 2008'09 की 3.80 करोड़ रूपए के अधि ोश के साथ आरम्भ होने और 7.01 करोड़ रूपए के अधि ोश के साथ समाप्त होने की सम्भावना हैं इस प्रकार वर्श के दौरान होने वाला लेन–देन 3.21 करोड़ रूपए का अधि ोश द ार्ाता है।

92. बजट अनुमानों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं और अन्य विकास योजनाओं के लिए 932.84 करोड़ रूप्ए के परिव्यय के प्रावधान के अतिरिक्त राज्य योजना के लिए 6650.00 करोड़ रूपए के परिव्यय की व्यवस्था है।

93. राजस्व खातों मैं, वर्श 2007–08 के बजट अनुमानों में प्राप्तियां 17917.35 करोड़ रूपए थी, जिनकी वर्श 2007–08 के सं ाोधित अनुमानों में बढ़कर 19629.69 करोड़ रूपए होने की संभावना है। वर्श 2008–09 के बजट अनुमानों में राजस्व प्राप्तियां 21695.32 करोड़ रूपए होने की संभावना है, जो 2007–08 के बजट अनुमानों से 3777.97 करोड़ रूपए अधिक है।

94. वर्श 2007–08 के बजट अनुमानों में राजस्व खर्च 16768.55 करोड़ रूप्ए द ार्शाया है, जिसकी वर्श 2007–08 के सं ाोधित अनुमानों में बढ़कर 18135.00 करोड़ रूपए हो जाने की संभावना है। वर्श 2008–09 के बजट अनुमानों में 20280.84 करोड़ रूपए का राजस्व खर्च द ार्शाया गया है, जो वर्श 2007–08 के बजट अनुमानों से 3512.29 करोड़ रूपए अधिक है। वर्श 2008–09 के बजट अनुमान 1414.48 करोड़ रूपए का राजस्व अधि ोश द ार्शाते है।

95. पूंजीगत खातों में, 2007–08 का खर्च 2983.31 रूपए है, जिसकी वर्श 2007–08 के सं ाोधित अनुमानों में बढ़कर 3385.64 करोड़ रूपए हो जाने की संभावना है। वर्श 2008–09 के बजट अनुमानों में पूंजीगत खर्च 3750.99 करोड़ रूपए है।

96. वर्श 2008–09 के बजट अनुमानों में राज्य के समेकित कोश में कुल प्राप्तियां 25987.40 करोउ़ रूपए की दिखाई गई है, जबकि वर्श 2007–08 के बजट अनुमानों में ये 21930.89

करोड़ रूपए और सं ाोधित अनुमानों में ये 20610.11 करोड़ रूपए है। वर्श 2008–09 के बजट अनुमानों में 26420.98 करोड़ रूपये का खर्च द ार्शाया गया है, जबकि वर्श 2007–08 के बजट अनुमानों में यह 21967.95 करोड़ रूपए और सं ाोधित अनुमानों में 22262. 45 करोड़ रूपए है।

97. आ ाा है कि करो के बढ़िया अनुपालन और अर्थ व्यवस्था में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप केन्द्रीय करों के हिस्से व अन्य अन्तरणों में वृद्धि होगी। इसी प्रकार राज्य के कर राजस्व में भी काफी वृद्धि होने का अनुमान है। मुझे वि वास है कि हम इस सदन के माननीय सदस्यों और प्रदे ा के लोगों के सहयोग और सहायता से प्रस्तावित योजनागत परिव्यय का पूरा उपयोग करके अपने सभी कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने में सफल होंगे।

98. महोदय, अब मैं वर्श 2008–09 के बजट अनुमानों को इस गरिमामय सदन के विचारार्थ तथा अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करता हूं।

जय हिन्द

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the House is adjourned till 9.30 A.M. tomorrow, on Wednesday the 19th March, 2008.

11.52 Hrs.

(The Sabha then *adjourned till 9.30 A.M. on Wednesday the 19th March, 2008.)